https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

भारत और फ्रांस के बीच हुए 14 प्रमुख समझौते

वर्ष-13, अंक-07 01-15 अप्रैल, 2018 (पाक्षिक) ₹20

'झूठ फैला रहा विपक्ष, जनता को सच बताएं'

'बीमार गरीबों का सहारा बनेगा आयुष्मान भारत'

'किसानों की आय दोगुनी करना हमारा लक्ष्य'

डॉ. भीमराव अंबेडकरः प्रखर राष्ट्रप्रेमी

वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में नौका–यात्रा करते फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

वाराणसी स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल का दौरा करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

वाराणसी में स्वच्छ भारत अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल 'कचरा महोत्सव' को देखते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व अन्य वरिष्ठ नेतागण

मणिपुर में आयोजित जनसभा में जनाभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **बीमार गरीबों का सहारा बनेगा आयुष्मान भारत : नरेन्द्र मोदी**

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब गरीबों को अपनी बीमारी को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। रुपयों के अभाव में इलाज कराने के बजाय...

वैचारिकी

शिक्षा: व्यक्ति निर्मात्री एवं समाज संचालिका 12

श्रद्धांजलि

सुन्दर सिंह भण्डारी 14

लेख

प्रगति की समीक्षा और अग्रगामी चर्चा 20
डॉ. भीमराव अंबेडकर: प्रखर राष्ट्रप्रेमी 22

अन्य

जनवरी, 2018 में औद्योगिक विकास दर 7.5 फीसदी 11
किसानों की आय दोगुनी करना हमारा लक्ष्य: नरेन्द्र मोदी 16
भारत और फ्रांस के बीच हुए 14 प्रमुख समझौते 18
मंत्रिमंडल ने यूरिया सब्सिडी को 12वीं पंचवर्षीय योजना... 24
पीएमएवाई (शहरी) के तहत शहरी गरीबों के लिए 3,21,567... 25
आमजन तक पहुंचाएं गुड गवर्नेंस का लाभ: वसुंधरा राजे 26
सिंचाई क्षमता बढ़ाने हेतु खर्च होंगे एक लाख दस हजार करोड़... 27
चौपालों और समाधान शिविरों के जरिये जनता से सीधा संवाद 28
प्रदेश सरकार ने एक वर्ष में किए महत्वपूर्ण कार्य : दिनेश शर्मा 29
ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय का उपयोग 93 % से ज़्यादा 30

स्थायी स्तंभ

सोशल मीडिया से 04
पत्र-पत्रिकाओं से 33
स्फुट विचार 33

संगठनात्मक गतिविधियां

08 **झूठ फैला रहा है विपक्ष, जनता को सच बताएं: नरेन्द्र मोदी**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि सरकार के बारे में झूठ...

15 **'ये योजनाएं राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगी'**

मणिपुर की राजधानी इंफाल में विभिन्न विकास योजनाओं के शिलान्यास के दौरान एक...

सरकार की उपलब्धियां

09 **पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन संपन्न**

भारत और फ्रांस की सह-मेजबानी में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन 11...

10 **थोक महंगाई सात महीने के सबसे निचले स्तर पर**

खाद्य वस्तुओं और सब्जियों की कीमतों में नरमी के कारण थोक मूल्य सूचकांक...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

सरकार इस बात का लगातार ध्यान रख रही है कि किसानों को आर्थिक मदद मिलने में कोई परेशानी न हो। 'स्वीट रिवॉल्यूशन' हमारे किसानों के लिए समृद्धि के द्वार खोल रहा है। मधुमक्खी पालन ना सिर्फ किसान की उपज बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि शहद के रूप में अतिरिक्त कमाई का साधन भी बनता है। 'वेस्ट टू वेल्थ' की दिशा में भी हमारी सरकार सार्थक प्रयास कर रही है। सोलर फार्मिंग भी एक और अवसर लेकर आया है। यह न सिर्फ सिंचाई की जरूरत को पूरा कर रहा है, बल्कि पर्यावरण की भी मदद कर रहा है।

@AmitShah

लंबे अरसे तक देश में अगर पंचायत से पार्लियामेंट तक की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रहती है तो देश को अनेक समस्याओं से मुक्त कर स्थितियों को पूर्ण रूप से बदला जा सकता है। जनता ने कांग्रेस को यह समय दिया था लेकिन उसने यह समय परिवार को बढ़ावा देने में बर्बाद कर दिया।

facebook

आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने सुशासन के माध्यम से 'सबका साथ, सबका विकास' करने का जो संकल्प लिया है, उसका पूरी तरह अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार भी जनता को जनार्दन मानकर उनकी सेवा कर रही है। उत्तर प्रदेश में यह पहली बार हो रहा है कि जब शासन की नीतियों और योजनाओं का आधार व्यक्ति, परिवार, जाति अथवा मजहब को न बनाकर गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिला सहित प्रदेश के दलित, वंचित और उपेक्षित वर्गों को बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार ने परिवर्तन, विकास और गरीबों के सशक्तिकरण के संकल्प के साथ 19 मार्च, 2017 को शपथ ली थी। इस प्रकार आज प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल का सफलतम एक वर्ष पूरा कर रही है। किसी भी राज्य में परिवर्तन, विकास और प्रगति के लिए मात्र 01 वर्ष की अवधि एक छोटा कार्यकाल है। सीमित संसाधनों के बीच उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए यह एक चुनौती भी है। इस चुनौती को हमने स्वीकार किया है।

— योगी आदित्य नाथ

चारा घोटाला के चौथे मामले में भी लालू प्रसाद का दोषी पाया जाना और 7-7 साल की लंबी सजा के साथ उन पर 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाना यह साबित करता है कि कोई व्यक्ति गलत तरीके से कितनी भी सम्पत्ति या राजनीतिक ताकत बटोर ले, वह कानून की पकड़ से बाहर नहीं जा सकता।

—सुशील कुमार मोदी

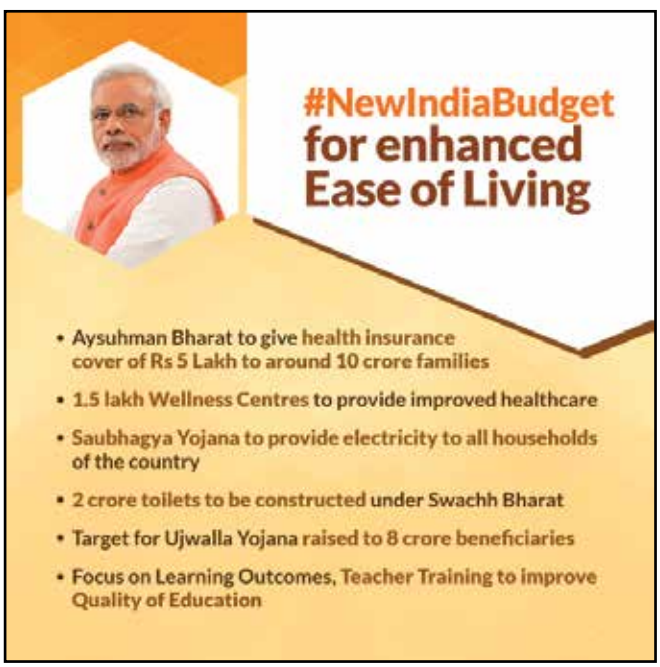

कांग्रेस ने खोया जन-विश्वास

नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन केवल शोर–शराबे का कार्यक्रम बनकर रह गया। हालांकि, कांग्रेस ने इस सच्चाई को स्वीकार किया कि वह भाजपा को अकेली टक्कर नहीं दे सकती, परन्तु जिन पार्टियों को आज वह समान विचारधारा वाली कह कर सहयोग लेने को आतुर है, उन्हीं को 1990 के मध्य में अपने राजनैतिक प्रस्ताव में राजनैतिक संवाद को प्रभावित करने वाले 'विभाजनकारी एजेंडे के साथ सतही ताकतें' बताने से नहीं चूकी। अपने अतीत का झूठा घमंड कांग्रेस को यह मानने नहीं दे रहा कि केवल कुछ पार्टियों को इकट्ठा कर वह जनता का विश्वास नहीं जीत सकतीं। उसे जनता का विश्वास इस देश की महान जनता द्वारा चलाये गये राष्ट्रीय आंदोलन से प्रवाहित होती लोकतांत्रिक एवं राष्ट्रवादी सिद्धांतों पर निष्ठा प्रमाणित करने पर ही प्राप्त होगा। कांग्रेस को यदि लगता है कि वह अपनी वंशवादी, भ्रष्ट, घिसे–पीटे सांप्रदायिक–जातिवादी–क्षेत्रवादी–विभाजक राजनीति से जनता को मूर्ख बना सकती है, तब यह कहने में कोई संशय नहीं कि वह भयंकर भूल कर रही है। केवल नकारात्मक राजनीति जनता को इसके करीब नहीं ला सकती, क्योंकि इससे यही पता चलता है कि कांग्रेस के पास देश के लिये कोई सकारात्मक कार्यक्रम नहीं है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे नीची ढलान पर है और इसे अब और नीचे जाने से कोई रोक नहीं सकता। इसका बार–बार देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान का रट लगाने से अब कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि अब सोनिया–राहुल की कांग्रेस वह कांग्रेस नहीं जो विदेशी शासन के विरुद्ध देश की आकांक्षाओं का प्रतिनिधि करती थी। स्वतंत्रता के बाद इसने अपने आप को सत्ता–केंद्रित राजनीति में डूबो दिया और देश को जाति, संप्रदाय, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटने लगी। अपने लंबे समय के कुशासन, भ्रष्टाचार, पॉलिसी पैरालिसिस और नकारात्मक नीतियों से इसने जनता का विश्वास खो दिया। कांग्रेस यह स्वीकार नहीं कर पा रही कि देश की सारी समस्याओं की जड़ इसकी ही असफल नीतियां और विभाजनकारी राजनीति रही है। इसने देश को हर क्षेत्र में पीछे कर दिया। इसकी असफल विदेश नीति देश को विश्व में एक उभरती शक्ति बन पाने में रूकावट बनी रही, क्योंकि इसकी अधिकतर नीतियां जमीनी सच्चाइयों से दूर रहीं तथा भारत को एक 'सॉफ्ट–स्टेट' बना दिया। आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा के मामले में भी कांग्रेस की नीतियां अस्पष्ट और ढीली–ढाली रही। जहां यूपीए सरकार 'पॉलिसी पैरालिसिस' से ग्रस्त रही, महत्वपूर्ण विषयों पर इसकी आर्थिक नीतियां दिशाहीन रही तथा भारी भ्रष्टाचार और सरकारी धन को लूट से स्थिति बद–से–बदतर होती गई। कृषि क्षेत्र की भयंकर उपेक्षा का ही परिणाम है कि आज देश के किसान कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कृषि की पूरी उपेक्षा के कारण ग्रामीण युवा शहरों को पलायन को मजबूर हुए, जिससे हजारों गांव तो उजड़े ही साथ में शहरों पर भारी बोझ बढ़ा। इसकी दिशाहीन आर्थिक–नीतियां एवं भयंकर लूट का ही परिणाम था कि देश की अर्थव्यवस्था पर संकट खड़ा हो गया। इसने कभी देश में न तो आत्मविश्वास पैदा किया, न ही भविष्य के लिए आशा की कोई किरण ही दिखाई, बल्कि देश को दहाई अंकों की मुद्रास्फीति तथा धीमी गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था बना दी।

> कांग्रेस ए.के. एंटोनी रिपोर्ट से भी कोई सीख नहीं ले पायी और इसे अपने हिन्दू–विरोधी एजेंडों को दुहराने की आदत पड़ गई है। अपने वैचारिक भटकाव और पार्टी की वंशवादी राजनीति से बचाने के उपायों पर मंथन करने के बजाए कांग्रेस ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से केवल मोदी–विरोधी, भाजपा–विरोधी राग ही पूरे अधिवेशन में अलापा है।

लोगों के लिये कांग्रेस की इस धोखाधड़ी के इतिहास को भुला पाना अब मुश्किल है। अपनी सत्ता को बचाये रखने के लिये इसने सभी सरकारी संस्थानों में राजनैतिक आधार पर अपने आदमी भरे तथा देश की प्रतिभा को इनसे बाहर रखा। हालांकि आज यह हिंदू धर्म की अच्छाई बांचने को बाध्य है और राहुल गांधी अपने राजनैतिक दौरों में मंदिरों की परिक्रमा भी कर रहे हैं, पर यह कोई नहीं भूल सकता कि 'सेकुलरिज्म' के नाम पर ये खुलेआम अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का खेल खेलते रहे हैं। हिंदुओं के गौरव के प्रति ये कितना समर्पित हैं, उनकी कर्नाटक सरकार द्वारा हिन्दुओं को बांटने के षड्यंत्र से ही साफ हो जाता है। लगता है कि ये स्वयं अपने ए. के. एंटोनी रिपोर्ट से भी कोई सीख नहीं ले पाये तथा इन्हें अपने हिन्दू–विरोधी एजेंडों को दुहराने की आदत पड़ गई है। अपने वैचारिक भटकाव और पार्टी की वंशवादी राजनीति से बचाने के उपायों पर मंथन करने के बजाए कांग्रेस ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से केवल मोदी–विरोधी, भाजपा–विरोधी राग ही पूरे अधिवेशन में अलापा है। इससे कांग्रेस का यह अधिवेशन केवल शोर–शराबे का कार्यक्रम बनकर रह गया और पार्टी में नई जान फूंकने में विफल साबित हुई है। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

बीमार गरीबों का सहारा बनेगा आयुष्मान भारत : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब गरीबों को अपनी बीमारी को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। रुपयों के अभाव में इलाज कराने के बजाय बीमारी को झेलना नहीं पड़ेगा। अब भारत सरकार बीमा कंपनियों के साथ मिल कर इसकी जिम्मेदारी उठाएगी। एक साल में पांच लाख तक के इलाज का खर्चा केन्द्र सरकार बीमा कंपनियों के साथ मिल कर उठाएगी। इसके लिए ही केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना लेकर आ रही है।

फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों के साथ 12 मार्च को बनारस पहुंचे श्री नरेन्द्र मोदी ने फ्रांसीसी मेहमान को गंगा में नौका विहार कराया। अस्सी से लेकर दशाश्वमेध घाट तक के बीच हुए नौका विहार के दौरान घाटों पर बनारस की संस्कृति से जुड़ी झांकियों ने राजनेताओं को अभिभूत कर दिया। उससे पूर्व दोनों राजनेता मीरजापुर गए, जहां फ्रांसीसी कंपनी के सहयोग से 650 करोड़ की लागत से स्थापित 75 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। मीरजापुर से लौट कर दोनों लोगों ने दीनदयाल हस्तकला संकुल जाकर बुनकरी और हस्तशिल्प के उत्पादों का अवलोकन किया। गंगा में नौका विहार के बाद नदेसर पैलेस में भोजन के दौरान श्री मोदी और श्री मैक्रों के साथ फ्रांस की फर्स्ट लेडी श्रीमती ब्रिगिट मैक्रों भी उपस्थित थीं।

इसके पश्चात् श्री नरेन्द्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डीजल रेल इंजन कारखाना पहुंचे और विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं को प्रमाण-पत्र, आवास की चाबी और चेक आदि दिया। श्री मोदी ने बनारस में करीब 800 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास कर सौगात दी।

इस दौरान भाषण में श्री मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से देश में निजी अस्पतालों की संख्या बढ़ेगी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोजगार भी बढ़ेगा। करीब 10 करोड़ परिवारों की चिंता खत्म होगी। मीरजापुर में सोलर प्लांट के बाबत श्री मोदी ने कहा कि हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है जब छतों पर सौर ऊर्जा के पैनल हों और रसोई में खाना उसी ऊर्जा से संचालित चूल्हे पर बने। न गैस की जरूरत होगी न पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। सूर्य की शक्ति का उपयोग बढ़ाना होगा हमें। उन्होंने इसके लिए आइआइटियंस का भी आह्वान किया कि वे इस दिशा में और इनोवेशन करें।

श्री मोदी ने काशीवासियों का आभार जताते हुए कहा कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति का जितना जोरदार स्वागत हुआ है उससे दोनों देश की दोस्ती और प्रगाढ़ होगी। इस दोस्ती पर काशी ने प्रेम वर्षा कर दी है।

डीरेका के मैदान में श्री मोदी ने कचरा महोत्सव का उद्घाटन

किया। इस दौरान कचरे से बने सजावटी सामानों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी श्री मोदी ने करीब 15 मिनट किया। मंच से बोले कि मुझे न पसंद करने वाले तंज कसेंगे कि मोदी अब कचरा महोत्सव कर रहे। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती। बस निकम्मी चीज का उत्तम प्रयोग करना सीखना होगा। वेस्ट में बेस्ट और कबाड़ से जुगाड़ की विधि अपनानी होगी।

प्रधानमंत्री ने मंडुआडीह रेलवे स्टेशन पहुंचकर बनारस से पटना के बीच नई ट्रेन मंडुआडीह-पटना जनशताब्दी को हरी झंडी दिखाई। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रेल राज्यमंत्री श्री मनोज सिन्हा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय भी उपस्थित थे।

डीरेका की सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदीजी के प्रयासों से देश में तेजी से विकास हो रहा है। यूपी में हम कचरा महोत्सव कर रहे हैं। कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती है। बस एक योग्य योजक की जरूरत होती है बेकार की चीजों को उपयोगी बनाने के लिए।

वाराणसी के एयरपोर्ट पर फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों तथा उनकी पत्नी का स्वागत करने वाले श्री नरेन्द्र मोदी ने उनके साथ मीरजापुर में सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने वाराणसी में गंगा नदी में नौका विहार किया।

वाराणसी के हस्तकला संकुल में श्री नरेन्द्र मोदी अपने विदेशी मेहमान के साथ जब यहां पहुंचे तो तबले की थाप पर शहनाई की मंगल ध्वनि से उनका स्वागत हुआ। वीवीआईपी ने संकुल में प्रवेश किया तो तो एक तरफ एंफीथिएटर में चित्रकूट का मंचन चला तो दूसरी तरफ पत्थर, काष्ठ, वस्त्र से जुड़े शिल्पी, बुनकर अपनी-अपनी विधाओं का सजीव प्रदर्शन किया।

मीरजापुर में प्रधानमंत्री के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 650 करोड़ की लागत से बने सौ मेगा वॉट के सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। यह प्लांट दादरकला में 650 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इस दौरान कंपनी के अधिकारियों ने प्लांट की विशेषताओं के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्रीय मंत्री व मीरजापुर से सांसद सुश्री अनुप्रिया पटेल भी उपस्थित थे। ■

झूठ फैला रहा है विपक्ष, जनता को सच बताएं: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि सरकार के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। श्री मोदी ने पार्टी सांसदों से तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 'विपक्ष के झूठ' का जवाब देने के लिए कहा। उन्होंने कहा, "विपक्ष कुंठित होकर सरकार के बारे में झूठ फैलाने का काम कर रहा है।"

श्री मोदी ने सांसदों से कहा कि वे तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जनता तक सच पहुंचाएं। वे अपने संसदीय क्षेत्रों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जनता को बताएं कि किस तरह विपक्ष संसद को काम करने से रोक रहा है।

गत 23 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के नये मुख्यालय, 6ए, पं. दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली में पार्टी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यह बात कही।

बैठक के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष संसद में गतिरोध पैदा कर रहा है और चर्चा नहीं कर रहा है। उन्होंने पार्टी सांसदों से जनता के बीच जाने और अगले तीन दिनों में अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में इन मुद्दों को उठाने और संवाददाता सम्मेलन करने को कहा। श्री शाह ने पार्टी संसदों से अपने-अपने क्षेत्र में बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने के साथ भाजपा की विचारधारा और मोदी के नेतृत्व में सरकार के जन-कल्याण एवं गरीबोन्मुखी योजनाओं को जमीन तक प्रचारित करना चाहिए।

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर और भाजपा मीडिया प्रमुख श्री अनिल बलूनी ने संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी। श्री जावडेकर ने कहा, "मोदीजी ने सांसदों से कहा कि पार्टी सत्ता में है ताकि हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकें और उन्होंने उनसे जमीन पर काम करने को कहा।"

श्री बलूनी ने कहा कि पार्टी 14 अप्रैल को बाबा साहब आंबेडकर की जयंती से पांच मई के बीच 'ग्राम स्वराज' अभियान कार्यक्रम का आयोजन करेगी। पार्टी 14 अप्रैल को सामाजिक न्याय दिवस का आयोजना करेगी और स्वच्छ भारत और उज्ज्वला योजना समेत सरकार की योजनाओं को लोगों के बीच पहुंचायेगी। श्री बलूनी ने कहा कि श्री जितेंद्र सिंह ने देश में 115 अति पिछड़े जिलों को विकसित करने पर सांसदों के सामने प्रस्तुतिकरण दिया। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले का दौरा करेंगे। आमतौर पर संसद सत्र के दौरान भाजपा संसदीय दल की बैठक हर मंगलवार को संसद भवन में होती है, पर इस मंगलवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक नहीं हुई और शुक्रवार को यह बैठक पार्टी के नए कार्यालय में हुई। ■

पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन संपन्न

भारत और फ्रांस की सह-मेजबानी में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन 11 मार्च को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के 61 देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और अपने बिजली उत्पादन स्रोतों में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्धता जताई। दरअसल, आईएसए सौर संसाधन संपन्न देशों का एक गठबंधन है, जो अपनी विशेष ऊर्जा जरुरतों को पूरा करने और दृष्टिकोण के माध्यम से अंतराल की पहचान कर उससे निपटने में सहयोग प्रदान करने के लिए मंच उपलब्ध कराएगा। आईएसए कर्क और मकर रेखा के ऊष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने वाले सभी देशों के लिए खुला है।

इस संस्थापक सम्मेलन में दिल्ली सौर एजेंडा पेश किया गया। एजेंडे में जोर दिया गया कि 'हमारे प्रयास में वृद्धि दर बढ़ाने, कौशल बढ़ाने, रोजगार पैदा करने, नवाचार बढ़ाने और आय बढ़ाकर स्थिरता हासिल करने की क्षमता है।' आईएसए सदस्य देश 'अपने राष्ट्रीय ऊर्जा खपत में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए प्रयासों में बढ़ोत्तरी पर' भी सहमत हुए।

एजेंडे में विकासशील देशों के लाभ के लिए सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थानों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी भागीदारी स्थापित करने समेत सस्ती वित्त व्यवस्था, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण तक पहुंच की बात कही गई।

सम्मेलन के दौरान भारत ने कहा कि उसने अपने सहयोगी देशों की व्यवहार्य परियोजनाओं की तैयारी में उनकी मदद के लिए परियोजना तैयारी सुविधा (पीपीएफ) की स्थापना की है, जिसके तहत रियायती ऋण सुविधा देने पर विचार किया जा सकता है। वर्तमान में भारत द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधा से 14.3 करोड़ डॉलर की 13 परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के संस्थापक सम्मेलन में भारत ने लगभग 27 प्रस्तावित परियोजनाओं की घोषणा की है, जिसके लिए 1.4 अरब डालर की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कहा कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का यह नन्हा पौधा आप सभी के सम्मिलित प्रयास और प्रतिबद्धता के बिना रोपा नहीं जा सकता था और इसलिए मैं फ्रांस का और आप सबका बहुत- बहुत आभारी हूं। 121 सम्भावित देशों में से 61 गठबंधन को ज्वाइन कर चुके हैं। 32 ने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को अनुमोदित भी कर दिया है, लेकिन इस गठबंधन में हम

सभी सहयोगी देशों के अलावा हमारे सबसे बड़े साथी हैं सूर्यदेवता, जो बाहर के वातावरण को प्रकाश और हमारे संकल्प को शक्ति दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे विश्व से नेताओं की आज यहां उपस्थिति इस बात की अभिव्यक्ति है कि सोलर एनर्जी मानव जाति की ऊर्जा जरुरतों को स्थायी रूप से पूरा करने का एक प्रभावी तथा किफायती समाधान उपलब्ध कराती है। उन्होंने कहा कि भारत में हमने दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम शुरू किया है। हम 2022 तक रिन्यूएबल्स से 175 गीगावाट बिजली उत्पन्न करेंगे, जिसमें से 100 गीगावाट बिजली सौर उर्जा से होगी। हमने इसमे से 20 गीगावाट स्थापित सोलर एनर्जी का लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया है। भारत में ऊर्जा की बढ़ोत्तरी अब परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बजाए रिन्यूएबल्स से अधिक हो रही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सोलर तकनीक के अंतर को भरने के लिए सोलर टेक्नोलॉजी मिशन भी शुरु करेगा। इस मिशन का अंतर्राष्ट्रीय फोकस होगा और यह हमारी सारी सरकारी, तकनीकी तथा शैक्षणिक संस्थाओं को साथ मिलाकर सोलर क्षेत्र में R&D प्रयासों का नेतृत्व करेगा। प्रचुर मात्रा में हवा की तरह उपलब्ध सोलर एनर्जी का विकास और प्रयोग हमारी समृद्धि के अलावा पृथ्वी का कार्बन भार अवश्य कम करेगा।

श्री मोदी ने कहा कि यदि हम पूरी पृथ्वी, पूरी मानवता की भलाई चाहते हैं तो मुझे विश्वास है कि निजी दायरों से बाहर निकलकर एक परिवार की तरह हम उद्देश्यों और प्रयासों में एकता और एकजुटता ला सकेंगे। यह वही रास्ता है जिससे हम प्राचीन मुनियों की प्रार्थना– 'तमसो मा ज्योतिर्गमय'– यानी हम अंधकार से प्रकाश को चलें, को चरितार्थ कर पायेंगे। ■

थोक महंगाई सात महीने के सबसे निचले स्तर पर

खाद्य वस्तुओं और सब्जियों की कीमतों में नरमी के कारण थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति फरवरी में 7 महीने के निचले स्तर 2.48% पर आ गई, जबकि जनवरी में थोक मुद्रास्फीति 2.84% और फरवरी 2017 में 5.51% थी। वित्त वर्ष में अब तक क्रमिक वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति दर 2.30 प्रतिशत आंकी गई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में क्रमिक वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति दर 4.92 प्रतिशत थी। विभिन्न जिंस समूहों के सूचकांक में उतार-चढ़ाव कुछ इस प्रकार रहे :-

प्राथमिक वस्तुएं (भारांक 22.62 प्रतिशत)

इस प्रमुख समूह का सूचकांक पिछले महीने के 129.7 अंक (अनंतिम) से 1.3 प्रतिशत घटकर 128.0 अंक (अनंतिम) रह गया। महीने के दौरान जिन समूहों और वस्तुओं के सूचकांक में उतार-चढ़ाव देखे गए, वे इस प्रकार हैं :

'खाद्य उत्पाद' समूह का सूचकांक पिछले महीने के 140.6 अंक (अनंतिम) से 2.0 प्रतिशत घटकर 137.8 अंक (अनंतिम) रह गया। ऐसा फल एवं सब्जियों (9 %), चना, चाय एवं मसूर (प्रत्येक 4%), राजमा एवं बाजरा (प्रत्येक 3%), अंडे, समुद्री मछली, मटर/चावली, ज्वार एवं उड़द (प्रत्येक 2%) और गेहूं (1%) के दाम घटने के कारण संभव हुआ। हालांकि, पान के पत्ते (13%), रागी (3%) और अरहर, मक्का, मसाले, कॉफी, मूंग, अंतदेर्शीय मछली, पोल्ट्री चिकन और धान (प्रत्येक 1%) के दाम बढ़ गए।

'गैर-खाद्य पदार्थ' समूह का सूचकांक पिछले महीने के 120.7 अंक (अनंतिम) से 0.1 प्रतिशत घटकर 120.6 अंक (अनंतिम) रह गया। ऐसा पुष्पकृषि (15%), नाइजर बीज (5%), कच्ची कपास एवं अलसी (प्रत्येक 3 प्रतिशत), कच्ची रबर, खाल (कच्ची) (प्रत्येक 2 प्रतिशत) और कपास बीज, कच्चे रेशम, सरसों बीज एवं कोपरा (नारियल) (प्रत्येक 1 प्रतिशत) के दाम घटने के कारण सभंव हुआ। हालांकि, सोयाबीन (11 प्रतिशत), मेस्ता (8 प्रतिशत), कच्चा जूट (5 प्रतिशत), ग्वार बीज (4 प्रतिशत), कच्चा ऊन एवं पशुचारा (प्रत्येक 2 प्रतिशत) और मूंगफली बीज, अरंडी बीज, तिल के बीज और सूरजमुखी (प्रत्येक 1 प्रतिशत) के दाम बढ़ गए।

'खनिज' समूह का सूचकांक पिछले महीने के 121.9 अंक (अनंतिम) से 0.2 प्रतिशत बढ़कर 122.2 अंक (अनंतिम) हो गया। ऐसा लौह अयस्क (3 प्रतिशत) और तांबा सांद्र (1 प्रतिशत) के दाम बढ़ने के कारण हुआ। हालांकि, सिलिमेनाइट (9 प्रतिशत), सीसा सांद्र (4 प्रतिशत), मैंगनीज अयस्क (3 प्रतिशत) और क्रोमाइट एवं फास्फोराइट (प्रत्येक 2 प्रतिशत) के दाम घट गए।

ईंधन एवं बिजली (भारांक 13.15 प्रतिशत)

इस प्रमुख समूह का सूचकांक पिछले महीने के 96.9 अंक (अनंतिम) से 1.2 प्रतिशत बढ़कर 98.1 अंक (अनंतिम) हो गया। इस महीने के दौरान विभिन्न समूहों एवं मदों में जो परिवर्तन देखे गए उनका उल्लेख निम्न है :

'कोयला' समूह का सूचकांक पिछले महीने के 121.1 अंक (अनंतिम) से 1.2 प्रतिशत बढ़कर 122.6 अंक (अनंतिम) हो गया। ऐसा गैर-कोकिंग कोल (2 प्रतिशत) का दाम बढ़ जाने के कारण हुआ।

निर्मित उत्पाद (भारांक 64.23 प्रतिशत)

इस प्रमुख समूह का सूचकांक पिछले महीने के 114.7 अंक (अनंतिम) से 0.4 प्रतिशत बढ़कर 115.2 अंक (अनंतिम) हो गया। इस महीने के दौरान विभिन्न समूहों एवं मदों में जो परिवर्तन देखे गए उनका उल्लेख नीचे किया गया है :

'खाद्य उत्पादों के निर्माण' का सूचकांक पिछले महीने के 126.8 अंक (अनंतिम) से 0.3 प्रतिशत घटकर 126.4 अंक (अनंतिम) रह गया। ऐसा शीरा (16%), प्रसंस्कृत चाय (7%), बेसन (6%), गुड़ (4%), चीनी (3%), मक्खन, सेवई, नूडल्स, मिल्क पाउडर, गरी तेल एवं अरंडी का तेल (प्रत्येक 2%) और शहद, रेपसीड ऑयल, फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण एवं संरक्षण, स्वास्थ्य पूरक का निर्माण, इन्स्टैंट कॉफी और आइसक्रीम (प्रत्येक 1 प्रतिशत) के दाम घटने के कारण संभव हुआ।

'वस्त्रों के निर्माण' समूह का सूचकांक पिछले महीने के 113.0 अंक (अनंतिम) से 0.6 प्रतिशत बढ़कर 113.7 अंक (अनंतिम) हो गया। ■

जनवरी, 2018 में औद्योगिक विकास दर 7.5 फीसदी

जनवरी, 2018 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) 132.3 अंक रहा, जो जनवरी, 2017 के मुकाबले 7.5 फीसदी ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि जनवरी, 2018 में औद्योगिक विकास दर 7.5 फीसदी रही। इसी तरह अप्रैल-जनवरी, 2017-18 में औद्योगिक विकास दर पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 4.1 फीसदी आंकी गई।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जनवरी, 2018 के लिए जारी किये गये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के त्वरित आकलन (आधार वर्ष 2011-12=100) से उपर्युक्त जानकारी मिली है। दरअसल, 14 स्रोत एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर आईआईपी का आकलन किया जाता है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और उर्वरक विभाग भी इन एजेंसियों में शामिल हैं।

जनवरी, 2018 में खनन, विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) एवं बिजली क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि दर जनवरी, 2017 के मुकाबले क्रमशः 0.1 फीसदी, 8.7 फीसदी तथा 7.6 फीसदी रही। इसी तरह अप्रैल-जनवरी 2017-18 में इन तीनों क्षेत्रों यानी सेक्टरों की उत्पादन वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में क्रमशः 2.5, 4.3 तथा 5.3 फीसदी आंकी गई।

उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार जनवरी, 2018 में प्राथमिक वस्तुओं (प्राइमरी गुड्स), पूंजीगत सामान, मध्यवर्ती वस्तुओं

एवं बुनियादी ढांचागत/निर्माण वस्तुओं की उत्पादन वृद्धि दर जनवरी, 2017 की तुलना में क्रमशः 5.8 फीसदी, 14.6 फीसदी, 4.9 फीसदी और 6.8 फीसदी रही। जहां तक टिकाऊ उपभोक्ता सामान का सवाल है, इनकी उत्पादन वृद्धि दर जनवरी, 2018 में 8.0 फीसदी रही है। वहीं, गैर-टिकाऊ उपभोक्ता सामान की उत्पादन वृद्धि दर जनवरी, 2018 में 10.5 फीसदी रही।

इस दौरान उच्च उत्पादन वृद्धि दर दर्ज करने वाली कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं में ट्रकों की बॉडी, लॉरी एवं ट्रेलर (267.5%), स्टेनलेस स्टील के बर्तन (89.2%), चीनी (40.9%), दोपहिया वाहन (मोटरसाइकिल/स्कूटर) (37.7 प्रतिशत), पाचन एंजाइम और एंटासिड (पीपीआई ड्रग्स सहित) (31.7%), वाणिज्यिक वाहन (29.8 प्रतिशत) और सीमेंट-सभी प्रकार (21.5 प्रतिशत) शामिल हैं। ■

किसानों की आत्महत्या के मामलों में 2016 में 10 फीसदी की कमी

किसानों द्वारा आत्महत्या करने के मामलों में वर्ष 2016 में 10 फीसदी की कमी आई है। कृषि मंत्रालय की तरफ से 20 मार्च को लोकसभा में पेश रिपार्ट के अनुसार वर्ष 2016 में देशभर में 11,370 किसानों ने आत्महत्या की, जबकि वर्ष 2015 में देश में 12,602 किसानों ने आत्महत्या की थी। इस तरह से एक साल के भीतर किसानों के आत्महत्या के मामलों में 10 फीसदी की कमी आई।

दरअसल, वर्ष 2016 में खरीफ फसलों की पैदावार अच्छी हुई थी, इस वजह से किसानों के आत्महत्या के मामलों में कमी आई। इससे पहले 2014 और 2015 में किसानों को सूखे का संकट झेलना पड़ा था, इस दौरान मानसूनी वर्षा सामान्य से 10 फीसदी कम और कई राज्यों में इससे भी कम हुई थी। जिसका असर खाद्यान्न उत्पादन पर पड़ा, जिससे कई राज्यों के किसानों को आर्थिक घाटा उठाना पड़ा था।

2015 में 4,595 कृषि मजदूरों ने तनाव के चलते मौत को गले लगा लिया, जबकि 2016 में यह आंकड़ा 5,019 हो गया। हालांकि, आत्महत्या के मामलों में कुल गिरावट किसानों के आत्महत्या में कमी के चलते आई। 2015 में कुल 8,007 किसानों ने अपनी जान दे दी, जबकि 2016 में यह आंकड़ा कम होकर 6,351 हो गया। ■

शिक्षा: व्यक्ति निर्मात्री एवं समाज संचालिका

| दीनदयाल उपाध्याय |

शिक्षा का संबंध जितना व्यक्ति से है, उससे अधिक समाज से। हम ऐसे मानव की कल्पना कर सकते हैं, जिसे किसी भी प्रकार की शिक्षा न मिली हो और जो अपनी सहज प्रवृत्तियों के सहारे ही जीवन-यापन करता हो, किंतु बिना शिक्षा के समाज संभव नहीं। किसी काल विशेष में कोई मानव समूह मात्र समाज की संज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता। उस समूह में प्रत्येक क्षण कुछ व्यक्ति घटते और कुछ बढ़ते रहते हैं। मानव की आयु मर्यादा के अनुसार एक कालावधि में किसी भी मानव समूह के सभी घटक भौतिक दृष्टि से बदल जाते हैं। किंतु इसके उपरांत भी यदि उस मानव समूह का व्यक्तित्व एवं उसकी चेतना बनी रहे, नए घटकों को पुराने घटकों से अपने संबंध का भान रहे तथा वे पुराने घटकों की जीवन की अनुभूति को अपनी अनुभूति मानकर और समझकर आगे चलें, तो उस समूह को 'समाज' नाम प्राप्त हो जाता है। अर्थात् एक के बाद एक मानव जब दूसरों को जो प्रायः उसके बाद जनमे हों, विभिन्न क्षेत्रों के अपने संपूर्ण अनुभव को अथवा उसमें के सारभूत अंश को विभिन्न उपायों द्वारा प्रदान या संसर्गित करता है, तो इस प्रक्रिया में एक निरंतर गतिमान मानव समूह की सृष्टि होती है, जिसे समाज कहते हैं। अनुभव प्रसारण की इस क्रिया को ही वास्तव में 'शिक्षा' कहते हैं। यदि शिक्षा न हो तो 'समाज' का जन्म ही न हो। अतः शिक्षा के प्रश्न को मूलतः सामाजिक दृष्टिकोण से ही देखना होगा। हमारे शास्त्रों के अनुसार यह ऋषि ऋण है, जिसे चुकाना प्रत्येक का कर्तव्य है। जब हम भावी संतति की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, वास्तव में हमारी उनके प्रति उपकार की भावना नहीं रहती, अपितु हमें जो कुछ धरोहर अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है, उसे आगे की पीढ़ी को सौंपकर उनके ऋण से उद्धरण होने की मनीषा रहती है। जॉन बुकन ने इसी भाव को इन शब्दों में व्यक्त किया है, हम भूत के ऋण से उऋण हो सकते हैं, यदि हम भविष्य को अपना ऋणी बनाएं।

शिक्षा संस्थाएं

'शिक्षा' की जितनी व्यापक और गहरी व्यवस्था होगी, समाज उतना ही अधिक पुष्ट और गंभीर होगा। नई पीढ़ी के जितने लोगों को और जितनी अधिक मात्रा में पिछली ज्ञान निधि प्राप्त होगी, उसी पूंजी को लेकर वह जीवन के कार्यक्षेत्र में उतरेगी। यह भी स्वाभाविक है कि वह प्राप्त पूंजी में अपने प्रयत्न और अनुभव के आधार पर वृद्धि करे। इस प्रकार यह पूंजी बराबर बढ़ती जाएगी। किंतु इसके लिए जहां शिक्षा की व्यापक और विविधतापूर्ण योजना करनी होगी, वहां 'प्रदेय' के असारभूत अंगों का परित्याग एवं तत्त्व का संरक्षण भी बड़े मनोयोग से करना होगा। एतदर्थ ऐसे लोगों की आवश्यकता हो जाती है, जो पीढ़ियों के संचित ज्ञान को आत्मसात् करके सुबोध बना सकें। 'शिक्षा' के व्यापक अर्थों में समाज का प्रत्येक घटक 'शिक्षक' होने के उपरांत भी उपर्युक्त कारणों से 'शिक्षण संस्था' का उदय हुआ।

राष्ट्र जीवन के 'मानस' का ज्ञान

प्रत्येक पीढ़ी के साथ समाज की प्राचीन निधि का संरक्षण, संवर्धन एवं आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरण होता रहता है। किंतु नई अनुभूतियों का जब तक प्राचीन अनुभूतियों के साथ एकीकरण नहीं होता, तब तक वे 'समाज' के मानस में स्थान नहीं पा सकतीं। यह तभी संभव है, जबकि समाज' के आज तक के संपूर्ण अनुभवों और जीवन व्यापारों का समन्वित, एकीकृत, सुसंबद्ध एवं सर्वांश में व्यापक ज्ञान प्राप्त हो। इस ज्ञान की छाप जितनी गहरी, सुस्पष्ट और सुव्यवस्थित रहेगी, उतना ही मानव अपनी जीवन यात्रा में सरलता और शांति से पग बढ़ा सकेगा। यदि उसको अपने राष्ट्र के 'मानस' का ठीकठीक ज्ञान नहीं हो तो वह अपने जीवन में सदैव ही उखड़ा-उखड़ा सा अनुभव करेगा।

शिक्षा के माध्यम

राष्ट्र मानस के ज्ञान अथवा शिक्षा के प्रमुख माध्यम हैं-1. संस्कार, 2. अध्यापन और 3. स्वाध्याय। मनुष्य अनजाने ही अपने चारों ओर के समाज से संस्कार ग्रहण करता रहता है। उसमें समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षक' का काम करता है। 'संस्कार' यद्यपि दोनों ओर से चलने वाली प्रक्रिया है, तथापि मानस की अनुकरण (Imitation), संवेदना (Sympathy) एवं सूचनात्मक (Suggestion) प्रवृत्तियों के नियम के अनुसार समर्थ कर्ता की क्रियाएं ही प्रभावकारी होती हैं। स्वभावतः पिछली पीढ़ी के आचार-विचारों का संस्कार नई पीढ़ी पर पड़ता है। माता-पिता, परिजन, पुरजन, गुरुजन, अग्रपाठी, सहपाठी, समाज के नेता और अधिष्ठाता ये सभी विभिन्न प्रकार से निरंतर संस्कार डालते रहते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उनकी क्रियाओं का परिणाम केवल उन पर ही नहीं, बल्कि अन्यों पर भी पड़ता है। स्वयं को ही नहीं, अन्यों को भी वे अपने कर्म बंधन में बांधते हैं।

अध्यापन व लोकशिक्षा

'अध्यापन' शिक्षा का सर्वसामान्य साधन है। साधारणतया' अक्षर ज्ञान' तथा पाठ्यपुस्तकों अथवा तत्संबंधी पाठ्यक्रम का अध्यापन ही इस क्षेत्र के अंतर्गत समझा जाता है। किंतु वास्तव में यह क्षेत्र भी बहुत विस्तीर्ण है। मानव के ज्ञान का बहुत ही थोड़ा अंश भाषा के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है और उसमें से भी एक अंश मात्र लिपिबद्ध है। अतः लिपि ज्ञान

अथवा भाषा ज्ञान से शिक्षा का पूर्ण उद्देश्य सिद्ध नहीं होता।' अध्यापन के अंतर्गत वे सब क्रियाएं आती हैं, जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपने पास के ज्ञान को दूसरे को देने का चेतनापूर्वक प्रयास करता हो। यह प्रयास पाठशालाओं और विश्वविद्यालयों में ही नहीं, घर-घर में तथा खेत-खलिहान, कारख़ानों, दुकानों, पाठशालाओं, कलाभवनों, खेल के मैदानों और मल्ल शालाओं में भी चलता रहता है। साथ ही जीवन के पहले आश्रम में ही नहीं, बाद में भी मनुष्य का विभिन्न प्रकार से अध्यापन होता रहता है। प्राचीन काल से कथा और कीर्तन तथा आज के रेडियो, सिनेमा, समाचार-पत्र आदि सभी इस सीमा में आते हैं।

स्वाध्याय

'स्वाध्याय' मनुष्य का स्वयं का अध्यापन है। लिपि ज्ञान स्वाध्याय के लिए बहुत आवश्यक है। पठन, मनन और चिंतन के सहारे मनुष्य ज्ञान को आत्मगम्य करता है। बिना स्वाध्याय के न तो प्राप्त ज्ञान टिकता है और न बढ़ता है। स्वाध्याय के बिना ज्ञान को जीवन का अंग बनाकर 'तेजस्वीय' बनाने का तो प्रश्न ही नहीं। अतः 'स्वाध्यायान्मा प्रमदः'- यह कुलपति का स्नातक को दीक्षांत के अवसर पर आदेश रहता था। पुस्तकालय आदि की व्यवस्था स्वाध्याय के लिए आवश्यक है।

शिक्षा का यदि सर्वांगपूर्ण विचार किया जाए तो शालेय शिक्षा क्रम तथा उसका माध्यम क्या हो, यह सहज ही समझा जा सकता है। व्यक्ति यदि भूत की ज्ञान निधि को भविष्य तक पहुंचाने वाला एक अभिकर्ता मात्र है, तो उसकी शिक्षा में इसका समावेश होना चाहिए। यदि यह नहीं हुआ तो वह समाज का चेतनशील एवं प्रभावी घटक होने के स्थान पर समाज से असंबद्ध एवं मृत प्राण जैसा होकर समाज के लिए अहितकर ही होगा।

शालेय शिक्षा अकेली ही मनुष्य का निर्माण नहीं करती। संस्कार और अध्यापन का बहुत सा क्षेत्र ऐसा है, जो शालेय क्षेत्र से बाहर है। यदि इन दोनों क्षेत्रों में विरोध रहा तो विद्यार्थी के जीवन में एक अंतर्द्वंद्व उपस्थित हो जाता है। एक समन्वित, एकीकृत, सर्वांगपूर्ण, अखंड व्यक्तित्व का विकास होने के स्थान पर उसकी प्रकृति में विभक्त निष्ठाओं का समावेश हो जाता है। समाज और उसके बीच एक खाई पड़ जाती है। इस दृष्टि से यह स्वाभाविक है कि शिक्षा का माध्यम स्वभाषा ही हो सकती है। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, वह स्वयं भी एक अभिव्यक्ति है। भाषा के एक-एक शब्द, वाक्य-रचना, मुहावरों आदि के पीछे समाज के जीवन की अनुभूतियां, राष्ट्र की घटनाओं का इतिहास छिपा हुआ है। फिर स्वभाषा व्यक्ति को अलग-अलग प्रकोष्ठों में नहीं बांटती।

शिक्षा के इस सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास किया गया तो व्यक्ति सहज ही चतुर्विध पुरुषार्थों के लिए प्रयत्न की योग्यता और सामर्थ्य प्राप्त कर लेगा। ■

-पांचजन्य, नवंबर 10, 1958

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अन्तर्गत 17 लाख से अधिक लाभार्थी नामांकित

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत नामांकित लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 17,66,423 हो गई है। नामांकन के लिए प्रतिदिन औसतन 50,000 आवेदन प्राप्त होते हैं। पीएमएमवीवाई के तहत सभी 36 राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए अब तक 2048.21 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 2042.09 करोड़ रुपये दे दिए गए हैं।

भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2017 से देश के सभी जिलों में पीएमएमवीवाई के कार्यान्वयन की मंजूरी दी जा चुकी है। पीएमएमवीवाई के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को 5,000 रुपये दिये जाते हैं और शेष राशि जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अंतर्गत मातृत्व लाभ की शर्तों के अनुरूप संस्थागत प्रसुति करवाने के बाद दी जाती है। इस प्रकार औसतन एक महिला को 6,000 रुपये प्राप्त होते हैं।

इस योजना के कार्यान्वयन के दिशानिर्देश, इस योजना को शुरू करने के सॉफ्टवेयर अर्थात प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सामान्य आवेदन सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाई-सीएएस) और इसकी नियमावली का शुभारंभ 1 सितम्बर, 2017 को माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी द्वारा किया गया था। पीएमएमवीवाई को राज्य सरकारों के सहयोग के कार्यान्वित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए मातृत्व लाभ उपलब्ध है। इसमे वे महिलाएं शामिल नहीं हैं, जो केन्द्र या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र को उपक्रमों में नियमित कर्मचारी हैं। इनके अलावा इस समय लागू किसी भी कानून के अंतर्गत इसी प्रकार का लाभ पाने वाली महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के उद्देश्य हैं: (i) गर्भवती महिला के वेतन में कटौती के लिए नगद प्रोत्साहन राशि के रुप में आंशिक मुआवजा प्रदान करना है, ताकि महिला पहले बच्चे के जन्म से पहले तथा बाद में पर्याप्त आराम कर सके; (ii) नगद प्रोत्साहन राशि से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता बढ़ेगी। ■

सुन्दर सिंह भण्डारी

(12 अप्रैल 1921 - 22 जून 2005)

शत शत नमन

सुन्दर सिंह भण्डारी का जन्म 12 अप्रैल 1921 को उदयपुर के एक जैन परिवार (राजस्थान) में हुआ। मूलतः उनका परिवार भीलवाड़ा के मण्डलगढ़ से संबंध रखता था, परन्तु उनके दादा वहां से उदयपुर चले गए थे। श्री भण्डारी के पिता डॉ. सुजान सिंह भण्डारी डाक्टरी पेशे से सबद्ध थे। इस कारण उन्हें सदैव घूमते रहना पड़ता था। श्री भण्डारी की शिक्षा कई स्थानों पर हुई। उन्होंने उदयपुर से सिरोही से इंटरमीडिएट परीक्षा पास की और डीएवी कॉलेज, कानपुर से बीए और एम.ए. किया। उन्होंने अर्थशास्त्र में एम.ए. पास किया और बाद में लॉ का अध्ययन किया।

श्री भण्डारी 'सरल जीवन और उच्च विचारों' के प्रतीक थे। शांत भाव के भण्डारी जीवन भर अविवाहित रहे और राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। 1942 में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मेवाड़ उच्च न्यायालय में लीगल प्रेक्टिस शुरू की। 1937 में उन्होंने एस. डी. कॉलेज, कानपुर में प्रवेश लिया, जहां पं. दीनदयाल उपाध्याय उनके सहपाठी थे। 1937 (दिसम्बर) में इंदौर के बालू महाशब्दे ने उन्हें कानपुर के निकट नवाबगंज की रा. स्व. संघ शाखा में ले गए थे। तब से वे अपनी अंतिम सांस तक रा.स्व.संघ की विचारधारा के प्रति समर्पित रहे।

1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। रा.स्व.संघ से जिन प्रमुख कार्यकर्ताओं को जनसंघ में कार्य के लिए भेजा गया था, उनमें उनका नाम प्रमुख रूप से शामिल था। 1951 से 1965 तक श्री भण्डारी ने राजस्थान जनसंघ में महामंत्री का दायित्व निभाया। इसके अलावा वे 1963 में जनसंघ के अखिल भारतीय मंत्री थे। पं. दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बाद 1968 में श्री भण्डारी जी को अखिल भारतीय महामंत्री (संगठन) बनाया गया।

भण्डारी जी ने कार्यकर्ताओं के सामने सरलता, सहनशीलता और मितव्ययता का उदाहरण पेश किया। वे अनुशासनप्रिय थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रतिबद्ध जीवन शैली की गरिमा बनाए रखने का आह्वान किया। वह एक ऐसे मूर्तिकार और कार्यकुशल-शिल्पी थे जिन्होंने मानव, समाज और संगठन की प्रतिमा बनाई।

उन्होंने 1977 तक जनसंघ महामंत्री के पद पर कार्य किया। वह 1966–1972 के समय राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। 1998 में उनका राज्य सभा का कार्यकाल समाप्त हुआ, तब उन्हें बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1999 में उन्हें गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया गया। भण्डारी जी ने कार्यकर्ताओं के सामने सरलता, सहनशीलता और मितव्ययता का उदाहरण पेश किया। वे अनुशासन प्रिय थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रतिबद्ध जीवन शैली की गरिमा बनाए रखने का आह्वान किया। वह एक ऐसे मूर्तिकार और कार्यकुशल शिल्पी थे जिन्होंने मानव, समाज और संगठन की प्रतिमा बनाई। वह कभी भी 'कलश' नहीं बनना चाहते थे। इसी कारण वे अत्यंत स्पष्टवादी थे। अपनी प्रकृति के कारण वे कार्यकर्ताओं में 'हैडमास्टर' के नाम से सुप्रसिद्ध हो गए। 22 जून 2005 को उनका स्वर्गवास हो गया। श्री भण्डारी ने अपने कालकाजी निवास पर प्रातः पांच बजे अंतिम सांस ली। उन्होंने अपना सारा जीवन मातृभूमि को समर्पित किया तथा जीवनभर रा.स्व.सं. प्रचारक बने रहे। उनके निधन से देश ने एक असाधारण राष्ट्रवादी गंवा दिया। ■

'ये योजनाएं राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगी'

मणिपुर की राजधानी इंफाल में विभिन्न विकास योजनाओं के शिलान्यास के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में किए गए विकास-कार्यों का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने मणिपुर की राज्य सरकार के काम करने के तरीके की जमकर प्रशंसा की। इस दौरान उन्होंने मणिपुर की महान क्रांतिकारी रानी गाइदिन्ल्यू को भी याद किया।

श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जिस तरह से मणिपुर के लोग खुश दिखते हैं, उससे पता चलता है कि राज्य सरकार कितनी अच्छी तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा, 'मणिपुर के विकास के लिए मुझे करीब 750 करोड़ की योजनाओं को शुरू करने या लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला। ये योजनाएं यहां के नौजवानों के सपनों और रोजगार, महिलाओं के सशक्तीकरण, और कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई हैं। मेरा विश्वास है ये योजनाएं राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगी।' मणिपुर की पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए श्री मोदी ने कहा कि पहले की सरकार की नीतियों और निर्णयों से समाज में जो नेगेटिविटी आ गई थी, उसे सीएम बिरेन की सरकार ने बदल दिया है। उन्होंने कहा कि लॉ ऐंड ऑर्डर, करप्शन, पारदर्शिता, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर मोर्चे पर मणिपुर सरकार तेजी से काम कर रही है।

श्री मोदी ने कहा कि इस राज्य की महिला शक्ति हमेशा देश के लिए प्रेरणा का एक स्रोत रही है। मोदीजी ने मणिपुर की महान क्रांतिकारी रानी गाइदिन्ल्यू को 'राष्ट्र की बेटी' कहकर संबोधित किया। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के लिए लड़कियों की समस्याओं को कम करने के लिए किए जा रहे कामों पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा, 'राज्य सरकार ने आदिवासी इलाके में लड़कियों के लिए एक नया छात्रावास का निर्माण किया है। ऐसे एक छात्रावास का उद्घाटन करने के लिए मैं खुद को भाग्यशाली हूं।'

श्री मोदी ने कहा कि भारत सरकार ने उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए दस भारतीय रिजर्व बटालियनों को मंजूरी दे दी है जिसमें मणिपुर के लिए दो बटालियन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये दो बटालियन सीधे राज्य में लगभग 2,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने 2014 वार्षिक सम्मेलन के दौरान पुलिस महानिरीक्षकों से आग्रह किया था कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पुलिस भर्ती में विशेष महत्व दिया जाए। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों की 136 महिला उम्मीदवारों सहित 438 उम्मीदवार दिल्ली पुलिस में शामिल हुए हैं।

श्री मोदी ने कहा कि राज्य में उनके द्वारा 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा, 'ये केंद्र हजारों माताओं और उनके बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक माध्यम के रूप में काम करेंगे।' श्री मोदी ने कहा कि 2014 की शुरुआत में राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की केवल 1200 किलोमीटर थी, लेकिन पिछले चार वर्षों में केन्द्र सरकार ने 460 किलोमीटर लंबी सड़क को नैशनल हाईवे के तौर पर घोषित किया है।

इससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इंफाल में 105वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में श्री मोदी ने वैज्ञानिकों से 100 बच्चों के साथ साल में 100 घंटे बिताने की भी अपील भी की। ■

किसानों की आय दोगुनी करना हमारा लक्ष्य: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 मार्च को नई दिल्ली के पूसा परिसर में आईएआरआई मेला ग्राउंड में आयोजित कृषि उन्नति मेला का दौरा किया। उन्होंने थीम पैवेलियन और जैविक मेला कुम्भ का भी दौरा किया। श्री मोदी ने 25 कृषि विज्ञान केंद्रों का शिलान्यास किया। साथ ही, उन्होंने जैविक उत्पादों के लिए एक ई-मार्केटिंग पोर्टल भी लांच किया। उन्होंने कृषि कर्मण पुरस्कार एवं पंडित दीन दयाल उपाध्याय कृषि प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए।

प्रधानमंत्री ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे उन्नति मेला नए भारत के लिए रास्ता प्रशस्त करते हैं। उन्होंने कहा कि आज उनके पास एक ही साथ नए भारत के दो प्रहरियों-किसानों एवं वैज्ञानिकों-से एक ही साथ बात करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि कृषि को रूपांतरित करने के लिए किसानों एवं वैज्ञानिकों को एक साथ मिलकर काम करने की जरुरत है।

श्री मोदी ने विशेष रूप से, मेघालय का उल्लेख किया जिसने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कृषि में अपनी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता के बाद से कृषि में उनकी उपलब्धियों के लिए हमारे किसानों की भावना और कड़ी मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज खाद्यान्नों, दलहनों, फलों एवं सब्जियों और दूध का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज कृषि क्षेत्र में कई प्रकार की विशाल चुनौतियां हैं, जो किसानों की आय घटाती हैं और उनके नुकसान और व्यय को बढ़ाती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक समग्र

दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य किसानों की आय को दोगुनी करना और किसानों के जीवन को सरल बनाना रहा है।

इस संकल्प की दिशा में अब तक हुई प्रगति के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तक 11 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। यूरिया के 100 प्रतिशत नीम लेपन का परिणाम भी उत्पादकता को बढ़ाने के अतिरिक्त, उर्वरक पर व्यय को कम करने के रूप में भी सामने आया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिये प्रीमियमों को कम किया गया है, बीमा पर अधिकतम निर्धारित सीमा खत्म कर दी गई है और किसानों को संवितरित किए जाने वाले दावों की राशि में बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में प्रत्येक खेत के लिए जल की परिकल्पना की गई है। सिंचाई क्षेत्र की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 80,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि किसान संपदा योजना खेत से बाजार तक आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने और आधुनिक कृषि अवसंरचना के सृजन में सहायता कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल के बजट में घोषित ऑपरेशन ग्रीन्स किसानों के लिए फलों एवं सब्जियों, खासकर, टमाटर, प्याज और आलू उगाने में लाभदायक होगा।

श्री मोदी ने कहा कि किसानों के कल्याण से संबंधित कई मॉडल कानून बनाये गए हैं और राज्यों से आग्रह किया गया है कि वे उन्हें कार्यान्वित करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने पर काम कर रही है कि किसानों को आधुनिक बीज, पर्याप्त बिजली

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिये प्रीमियमों को कम किया गया है, बीमा पर अधिकतम निर्धारित सीमा खत्म कर दी गई है और किसानों को संवितरित किए जाने वाले दावों की राशि में बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में प्रत्येक खेत के लिए जल की परिकल्पना की गई है। सिंचाई क्षेत्र की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 80,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

आपूर्ति एवं सरल बाजार सुविधा हासिल हो सके।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि सभी अनुसूचित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागत से कम से कम डेढ़ गुना होगा। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए लागत में श्रम, मशीनरी का किराया, बीजों एवं उर्वरकों की लागत, राज्य सरकार को दिया जा रहा राजस्व, कार्यशील पूंजी और पट्टे पर दी गई भूमि का किराया जैसे तत्व शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि विपणन सुधारों के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। ग्रामीण रिटेल बाजारों को थोक और वैश्विक बाजारों के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हाल के आम बजट में ग्रामीण रिटेल कृषि बाजारों की परिकल्पना की गई है। 22,000 ग्रामीण हाटों को आवश्यक अवसंरचना के साथ समुन्नत किया जाएगा एवं एपीएमसी तथा ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ समेकित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने किसान उत्पादक संगठनों के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि किसान उत्पादक संगठनों को कॉपरेटिव सोसाइटीज की तर्ज पर आय कर में राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में जैविक उत्पादों के लिए ई-मार्केटिंग पोर्टल के साथ कृषि विपणन सुधार में एक नया अध्याय जोड़ा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस दिशा में कृषि विज्ञान केंद्र भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि फसलों के अवशेषों को जलाने का हानिकारक प्रभाव पड़ता है और अगर मशीनों के जरिये इसे फिर से मृदा को वापस कर दिया जाए तो इसके लाभदायक प्रभाव होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि पर्याप्त कृषि ऋण उपलब्ध हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समारोह दूर-दराज के क्षेत्रों में भी आयोजित किए जाने चाहिए। ■

भारत और फ्रांस के बीच हुए 14 प्रमुख समझौते

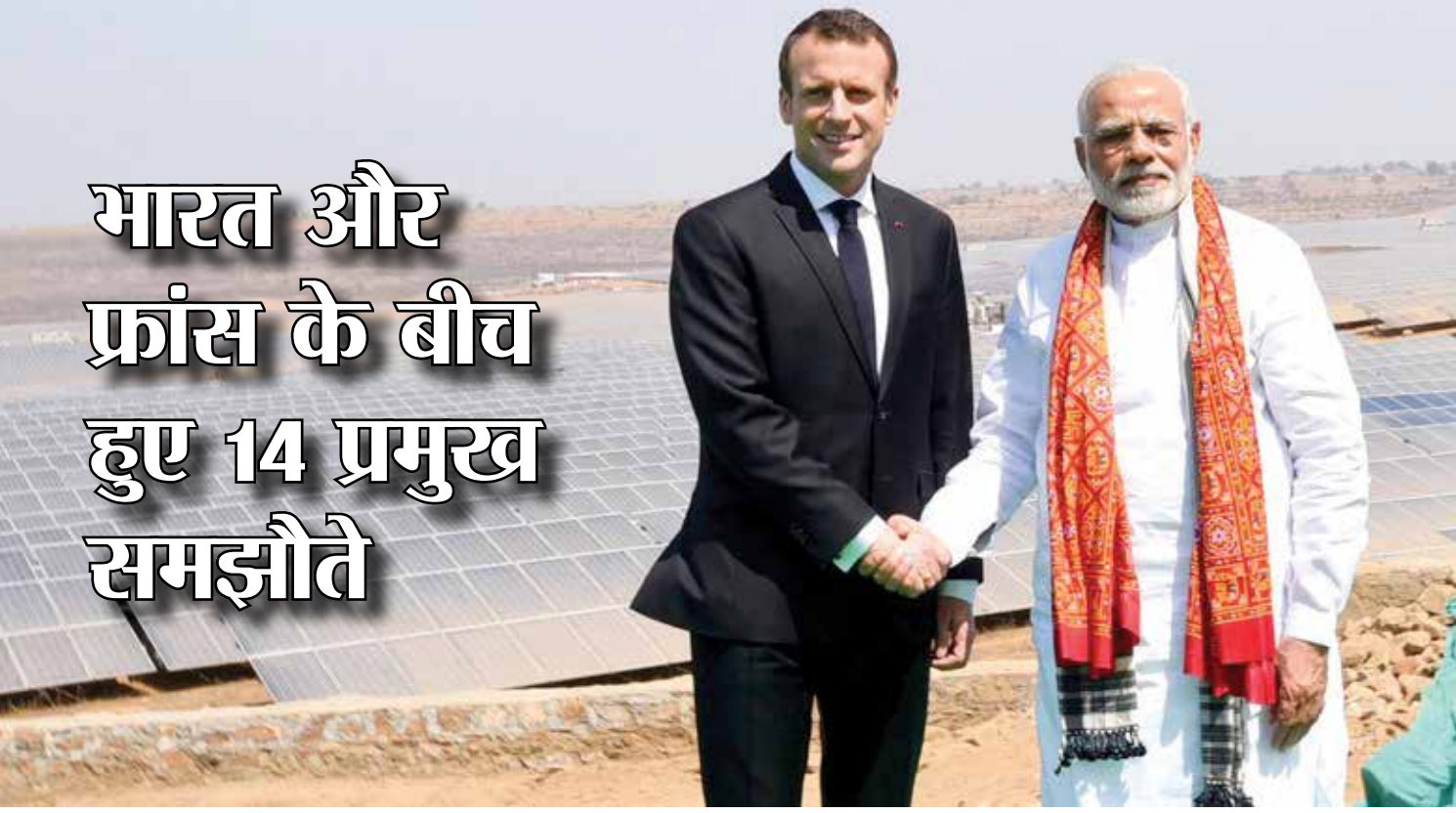

फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रों चार दिन की राजकीय यात्रा पर 9 मार्च को भारत आए। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 14 प्रमुख समझौते हुए। राष्ट्रपति श्री मैक्रों ने दिल्ली में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और वाराणसी में गंगा के दर्शन भी किए।

फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रों चार दिन की यात्रा पर 9 मार्च को भारत पहुंचे। नई दिल्ली में एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनकी अगवानी की। 10 मार्च को राष्ट्रपति श्री मैक्रों और प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 14 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते रेलवे, शहरी विकास, रक्षा, अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों में किए गए। इनमें भारत और फ्रांस के बीच सशस्त्र बलों में पारस्परिक लॉजिस्टिक्स समर्थन के प्रावधान के संबंध में समझौता, भारत और फ्रांस के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन, अकादमिक योग्यता के परस्पर मान्यता की सुविधा के लिए भारत और फ्रांस के बीच समझौता और नशीली दवाओं, मनोवैज्ञानिक पदार्थों और रासायनिक प्रणेताओं अवैध सेवन तथा संबंधित अपराधों और अवैध आवागमन की रोकथाम पर भारत और फ्रांस के बीच समझौता प्रमुख है।

दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'हम सिर्फ दो सशक्त स्वतंत्र देशों और दो विविधतापूर्ण लोकतंत्रों के ही नेता नहीं हैं, हम दो समृद्ध और समर्थ विरासतों के उत्तराधिकारी हैं।' उन्होंने कहा, 'हमारी (भारत-फ्रांस) रणनीतिक भागीदारी भले ही 20 साल पुरानी हो, हमारे देशों और हमारी सभ्यताओं की आध्यात्मिक साझेदारी सदियों लंबी है।'

श्री मोदी ने कहा कि 18वीं शताब्दी से लेकर आज तक, पंचतंत्र की कहानियों के ज़रिये, वेद, उपनिषद, महाकाव्यों श्री रामकृष्ण और श्री अरबिंद जैसे महापुरुषों के ज़रिये, फ्रांसीसी विचारकों ने भारत की आत्मा में झांककर देखा है। वोल्तेयर (Voltaire), विक्टर ह्युगो, रोमां रोलां, रेने दौमाल, आंद्रे मलरो जैसे असंख्य युगप्रवर्तकों ने भारत के दर्शन में अपनी विचाराधाराओं का पूरक और प्रेरक पाया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्रांस और भारत की एक मंच पर उपस्थिति एक समावेशी, खुले, और समृद्ध व शान्तिमय विश्व के लिए सुनहरा संकेत है। हमारे दोनों देशों की स्वायत्त और स्वतंत्र विदेश नीतियां सिर्फ अपने-अपने हित पर ही नहीं, अपने देशवासियों के हित पर ही नहीं, बल्कि सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को सहेजने पर भी केंद्रित है। और आज वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए यदि कोई दो देश कंधे से कंधा मिला कर चल सकते हैं, तो वे हैं भारत और फ्रांस।

फ्रांस के राष्ट्रपति ने की गंगा की सैर

भारत दौरे के अंतिम दिन वाराणसी पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ गंगा की सैर की। दोनों अस्सी घाट के साथ ही दशवाश्वेमध घाट पर भी घूमे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। श्री मोदी ने अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल लगभग 300 करोड़ रुपये

भारत और फ्रांस के बीच अकादमिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता पर ऐतिहासिक समझौता

प्रथम भारत-फ्रांसीसी ज्ञान शिखर सम्मेलन 'दोनों देशों के बीच अकादमिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता' पर एक ऐतिहासिक समझौते और संयुक्त पहलों एवं साझेदारियों पर विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के बीच रिकॉर्ड 15 अन्य समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। गौरतलब है कि दो दिवसीय शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसका आयोजन संयोगवश फ्रांस के राष्ट्रपति श्री एमैनुएल मैक्रों की आधिकारिक भारत यात्रा के दौरान ही हुआ।

यह शिखर सम्मेलन भारत में फ्रांसीसी दूतावास द्वारा आयोजित किया गया और भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसकी सह-मेजबानी की गई। लगभग 80 भारतीय संस्थानों और 70 फ्रांसीसी संस्थानों के 350 से भी अधिक लोगों ने प्रमुख उद्यमों के साथ इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया जिसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कैंपस फ्रांस और भारतीय उद्योग परिसंघ का भी समर्थन प्राप्त हुआ।

समापन सत्र में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने दोनों सरकारों को अकादमिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता पर समझौते को अंतिम रूप देने में सहयोग देने के लिए बधाई दी। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच शैक्षणिक संबंध को बढ़ावा देने, अन्य देश में अपनी पढ़ाई जारी रखने हेतु उनके लिए संभावनाओं को सुविधाजनक बनाकर दोनों देशों के छात्रों की गतिशीलता को प्रोत्साहित करने और सहयोग, विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संबंधी आदान-प्रदान के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने में काफी मददगार साबित होगा।

श्री जावड़ेकर ने यह भी कहा कि सरकार जल्द ही और अधिक विदेशी छात्रों को भारत में शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए ' भारत में अध्ययन कार्यक्रम' का शुभारंभ करेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत में 47000 विदेशी छात्र अध्ययन कर रहे हैं और वर्ष 2022 तक भारत में कम से कम 100,000 विदेशी छात्र अध्ययन करने लगेंगे।

श्री जावड़ेकर ने यह सुझाव भी सामने रखा कि दोनों देशों को पारस्परिकता के आधार पर प्रोफेशनलों को एक-दूसरे के देश में प्रैक्टिस करने की अनुमति देने पर विचार करना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्री ने यह जानकारी दी कि शिक्षा और शोध में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच एक संयुक्त कार्यदल (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेडब्ल्यूजी की बैठक सितंबर में होगी। उच्च शिक्षा और अनुसंधान एवं नवाचार मंत्री फ्रेडरिक विडाल ने समापन सत्र में अपनी टिप्पणी में कहा कि गरीबी और असमानता से लड़ने में शिक्षा एक प्रभावकारी हथियार बन सकती है।

उल्लेखनीय है कि यह ज्ञान शिखर सम्मेलन विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए प्रथम फ्रांस-भारत शिखर सम्मेलन है, जिसका उद्देश्य कंपनियों के सहयोग से अगले पांच वर्षों के लिए फ्रांस-भारत सहयोग का एक रोडमैप तैयार करना है।

इससे पहले, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल और माननीया फ्रेडरिक विडाल के नेतृत्व में फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल ने एक द्विपक्षीय बैठक की। प्रतिनिधिमंडल स्तर की इस बैठक में भारत एवं फ्रांस के उच्च शैक्षणिक संस्थानों के बीच साझेदारी बढ़ाने तथा 'ज्ञान' कार्यक्रम के तहत फ्रांसीसी शिक्षाविदों की और अधिक भागीदारी, इत्यादि पर चर्चाएं हुईं।

की लागत से निर्मित पंडित दीन दयाल हस्तकला संकुल में बनारसी साड़ी, मीनाकारी, कड़ी के खिलौने, पत्थर कृतियां, संगीत सहित पूर्वांचल की खास पहचान माने जाने वाले धार्मिक धरोहरों से श्री मैक्रों को रुबरू करवाया।

इससे पहले श्री मैक्रों और श्री मोदी ने 800 करोड रुपये से अधिक की लागत से बने भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का विन्ध्य की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच उद्घाटन किया। गौरतलब है कि विजयपुर स्थित दादरकला में स्थापित इस प्लांट में पांच लाख 86 हजार 382 प्लेट्स लगाये गये हैं। 75 मेगावाट के इस सोलर प्लान्ट का फ्रासींसी कंपनी इनर्जी सोलर ने निर्माण किया है। इसमें 800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आयी है। ■

प्रगति की समीक्षा और अग्रगामी चर्चा

विनय सहस्त्रबुद्धे
धीरज नय्यर

ऐसा कभी–कभार होता है कि कोई प्रधानमंत्री परियोजना के कार्यान्वयन और निगरानी पर इतनी बारीकी से नजर रखता है, परन्तु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए यह सामान्य सी बात है। दरअसल, भारत में सरकारों का इतिहास अच्छे विचारों, लेकिन गलत कार्यान्वयन से भरा पड़ा है। ऐसी स्थिति इस बार नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के प्रति गंभीरता से जिम्मेदारी लेते हैं।

15 मार्च 2015 से हर महीने प्रधानमंत्री सरकारी कार्यान्वयन मशीनरी के सम्मेलन करते रहते हैं, जिसमें विभिन्न विभागों के मंत्रालय और विभाग तथा 29 राज्यों और सात केन्द्र–शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासक शामिल रहते हैं। एक या दो घण्टों से भी ज्यादा समय में प्रधानमंत्री सीधे सामाजिक शिकायतों के सम्बन्ध में चर्चा करते हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा करते हैं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जांच करते हैं।

प्रगति का समन्वयन मंत्रालयों, केन्द्रीय सरकारी विभागों और राज्य सरकारों के बीच एक पूर्ण नए स्तर पर रहता है। कुल मिलाकर वीडियो कांफ्रेंसिंग, डिजिटल डाटा प्रबंधन और भौगोलिक सूचना व्यवस्था से प्रधानमंत्री कार्यालय केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कारनामों को सही समय पर खोज निकालती है, जिससे जमीनी स्थिति के वर्तमान सूचना और नवीनतम विजुअल का पता लगता रहता है। अधिकारीगण एक दूसरे से सूचनाओं का आदान–प्रदान करते हैं और रुकावटों पर चर्चा होती है और इस बात की तैयारी की जाती है कि कैसे इनका समाधान हो सके। प्रधानमंत्री द्वारा सीधा हस्तक्षेप करने से परिणाम सामने आते हैं।

इस व्यवस्था पारदर्शिता और जिम्मेदारी का अहसास होता है और जो सहकारी संघवाद की भावना के अनुकूल होता है। इससे राज्य स्तरीय अधिकारीगण केन्द्रीय सरकार के आमने सामने आते हैं और केन्द्रीय सरकार के सचिवों और प्रधानमंत्री कार्यालय तीनों पक्षों के बीच इसके कार्यान्वयन और डिलीवरी के विषय पर विचार करने में समर्थ होते हैं। इससे जटिल, बहु–आयामी निर्णय लेने की स्थिति से बचा जा सकता है और स्टेकहोल्डरों की एक–दूसरे की प्राथमिकताओं के बीच समाधान किया जा सकता है।

जरा इससे पहले की 'प्रगति' बैठकों पर ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिजिटल छवि सम्मेलन कक्ष पर प्रभावी रहती है, जहां जम्मू–कश्मीर के वरिष्ठ अधिकारी बांदीपुरा जिले में कृष्णगंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना पर विचार करने के लिए जमा हुए थे। मुख्य सचिव ब्रजराज शर्मा और उनकी टीम सूट और जैकेटों में थी, प्रधानमंत्री 'मोदी कुर्ता' में थे जबकि अभी भी दिल्ली में लम्बी बांह का कुर्ता पहनने की स्थिति थी।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दस लोगों का समूह था जो सीधे प्रधानमंत्री के सामने था। दस और भागीदारी भी डिजिटल रूप से उनके साथ भागीदार बने हुए थे। 2015 की बात है और प्रधानमंत्री इस बात के लिए उत्सुक थे कि कृष्णगंगा संयंत्र अविलम्ब शुरू किया जा सके। अभी तक, यह परियोजना की स्थिति खराब रही थी और पाकिस्तान ने 'हेग' में अपील की थी, परन्तु जैसे–तैसे भारत ने अपना बन्दोबस्त बनाए रखा।

15 मार्च 2015 से हर महीने प्रधानमंत्री सरकारी कार्यान्वयन मशीनरी के सम्मेलन करते रहते हैं, जिसमें विभिन्न विभागों के मंत्रालय और विभाग तथा 29 राज्यों और सात केन्द्र–शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासक शामिल रहते हैं। एक या दो घण्टों से भी ज्यादा समय में प्रधानमंत्री सीधे सामाजिक शिकायतों के सम्बन्ध में चर्चा करते हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा करते हैं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जांच करते हैं।

330 मैगावाट परियोजना की स्थिति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया था कि 382 हेक्टेयर में से केवल तीन का अधिग्रहण किया जा सकता है, जिससे 185 परिवारों को विस्थापित करना पड़ा है। उनके पुनर्वास की योजना तैयार की गई है, परन्तु दुर्भाग्य से यह असफल रहा है और इसमें संशोधन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने विद्युत सचिव को जम्मू–

कश्मीर के साथ समन्वय करने की सलाह दी, ताकि परियोजना पर शीघ्र काम शुरू हो सके और विस्थापित लोगों को वहां आराम से बसाया जा सके।

कई परियोजनाओं में किशनगंगा भी एक परियोजना थी, जिसकी प्रधानमंत्री ने 30 सितंबर 2015 की छठी बैठक में चर्चा की। देशभर के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के अपने सामने सीधे इस परियोजनाओं के समक्ष समाधान प्रस्तुत किया।

'प्रगति' से पूर्व, केन्द्र और राज्य स्तर के अधिकारी संघर्ष करते रहे जिनमें संचार सम्बन्धी अनेक कमियां थीं और इन कमियों से यह प्रमुख योजनाएं प्रभावित हो रही थीं। इन कमियों के कारण प्रमुख परियोजनाओं को हानि हो रही थी और विलम्ब भी हो रहा था। इन कमियों के कारण योजनाओं की लागत बढ़ रही थी, जिससे अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव बन रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं समय न रहते नुकसान उठा रहीं थीं और लागत बढ़ती जा रही थी और लागत बढ़ रही थी, जिससे अन्य अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टरों पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ा।

समन्वय, सूचना और समयोगत संचार की कमी के कारण कुसंस्कृति पैदा हो गई। इस प्रस्ताव से कोई भी विचार स्पष्ट रूप में सामने नहीं आ सका और न ही तेजी से उसका कार्यान्वयन हो सका। इस प्रकार परियोजनाओं का नियमित समीक्षा नहीं हो सकी, जिससे विलम्ब की जिम्मेदारी कभी भी निश्चित नहीं हो पाई।

परियोजना की लगातार समीक्षा और समाधान की तत्काल आवश्यकता थी, ताकि सरकार कार्यक्रमों का विस्तार कर सके। इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए वर्तमान डाटा हेतु वीडियो कांफ्रेंसिंग की व्यापक आवश्यकता थी। एक बार प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इंटरएक्टिव मानीटरिंग प्लेटफॉर्म की आवश्यकता जताने पर नेशनल इंफोरमेटिक्स सेंटर ने 'प्रगति' का डिजाइन तैयार कर लिया। पहला कदम यह सुनिश्चित करना था कि सभी सचिवों और मुख्य सचिवों को वीडियों कांफ्रेंसिंग की सुविधा मिले। यह तय किया गया कि हर महीने चौथे बुधवार को 3.30 बजे इसका आयोजन हो, जिसे 'प्रगति' का नाम दिया जाए।

यह प्रक्रिया इस प्रकार से है: वीडियो कॉफ्रेंस से एक सप्ताह पूर्व पीएमओ और राज्य सरकारें अपलोड करें। प्रत्येक सचिव मुख्य सचिव के पास उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड होता है, जिससे वह अपने विभाग से संबंधित मुद्दे जमा करता है और इन्हें तीन दिन के अंदर कमेंट पोस्ट या अपडेट करना होता है। बैठक से पहले जीएम उनकी प्रविष्टि की समीक्षा करते हैं।

जब प्रधानमंत्री किसी परियोजना की समीक्षा करते हैं, तो सम्बंधित अधिकारी व्यापक डिटेल और नवीनतम स्थिति का व्यापक व्याख्या सामने रखते हैं और पीएमओ कांफ्रेंस चैम्बर में तीन स्क्रीनों में से एक पर उसे चढ़ाते हैं, जहां अधिकारीगण यू–आकार की मेज पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठे होते हैं। बैठक में एजेंडा के प्रत्येक मद को दोहराया जाता है।

उदाहरणार्थ, कृष्णगंगा परियोजना की चर्चा करने के बाद, प्रधानमंत्री ने प्रोसेसिंग पेटेंट और ट्रेडमार्क आवेदनों में 'अनुचित' विलम्ब की बात की। उन्होंने कहा कि विश्वस्तरीय और अनुकूल स्थिति बैठाने और ओवरहाल करने की आवश्यकता है, जिसमें कई फार्मों की संख्या कम करना आवश्यक है। इन्होंने सत्रह राज्यों में सोलर ऊर्जा कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया और अध्यक्षीय अधिकारियों से कहा कि उनके लिए समुचित हालात तैयार करना जरूरी है, ताकि इनका तेजी से कार्यान्वयन हो सके।

अफगानिस्तान में भारतीय परियोजना पर बात करते हुए उन्होंने संसद भवन और सलमा बांध की प्रगति को जोरदार ढंग से पूरा करने की बात की। उन्होंने 'सार्क' क्षेत्र में सभी भारतीय कारनामों पर तेजी से काम करने के महत्व पर जोर दिया।

'प्रगति' के दौरान प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं जैसे- मेट्रो रेल, कोयला और लौह खनन, सड़क, विद्युत और उड़ान क्षेत्र भी चर्चा में आए। इनमें लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना (फेज ए) शामिल रहा जिसे प्रधानमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। इसके अलावा समीक्षा में खुर्दा–बोलंगीर ब्रॉड गेज लिंक, मुम्बई मेट्रो परियोजनाओं लाइन 3 (कोलाबा–बांद्रा–सीटज) और सिक्किम में पाकयंग हवाई अड्डा शामिल रहा, जिसे उन्होंने टूरिज्म कनेक्टिविटी और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक माना।

दरअसल, 'प्रगति' के दौरान प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं जैसे- मेट्रो रेल, कोयला और लौह खनन, सड़क, विद्युत और उड़ान क्षेत्र भी चर्चा में आए। इनमें लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना (फेज ए) शामिल रहा जिसे प्रधानमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। इसके अलावा समीक्षा में खुर्दा–बोलंगीर ब्रॉड गेज लिंक, मुम्बई मेट्रो परियोजनाओं लाइन 3 (कोलाबा–बांद्रा–सीटज) और सिक्किम में पाकयंग हवाई अड्डा शामिल रहा, जिसे उन्होंने टूरिज्म कनेक्टिविटी और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक माना। ■ जारी...

(उपरोक्त सामग्री सद्य: प्रकाशित पुस्तक
'द इनोवेशन रिपब्लिक' से साभार प्रस्तुत है)

प्रखर राष्ट्रप्रेमी

| संजीव कुमार सिन्हा |

डॉ. भीमराव अंबेडकर का व्यक्तित्व बहुत विराट् था। वे एक विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक तो थे ही, साथ ही प्रखर राष्ट्रप्रेमी भी थे। उनके विचार भारतीयता से ओत–प्रोत थे। वे सामाजिक एकता को राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक मानते थे। बाबा साहब ऐसा समाज चाहते थे जिसमें सामाजिक व आर्थिक असमानता न हो और इसके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन संघर्ष में बिता दिया। उनका नजरिया व्यापक था। दुर्भाग्य से उनके बारे में एक धारणा बना दी गई कि वे केवल वंचितों के मसीहा थे, यह उनके समग्र योगदान को देखते हुए उनके साथ न्याय नहीं है। वे किसी वर्ग विशेष की नहीं परंतु समस्त भारतीय जन की आवाज थे। अखंड भारत और समान नागरिक संहिता का समर्थन, अनुच्छेद 370 का विरोध, देश की राजभाषा संस्कृत हो, आर्य बाहर से नहीं आए थे, धर्म में अटूट विश्वास जैसे उनके अनेक प्रखर विचार यह सिद्ध करते हैं कि उनके राष्ट्र सर्वोपरि था।

राष्ट्रप्रेम : डॉ. अंबेडकर का दृढ़ मत था कि मैं हिंदुस्तान से प्रेम करता हूं। मैं जीऊंगा तो हिंदुस्तान के लिए और मरूंगा तो हिंदुस्तान के लिए। मेरे शरीर का प्रत्येक कण और मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण हिंदुस्तान के काम आए, इसलिए मेरा जन्म हुआ है। उनके अनुसार, जब तक सामाजिक समरसता का भाव पूर्णतः राष्ट्र में उत्पन्न नहीं होगा तब तक राष्ट्रवाद की स्थापना नहीं हो पाएगी।

डॉ. अंबेडकर का मानना था कि राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग के अंतर को भूलकर उनमें सामाजिक भ्रातृत्व की भावना को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। (डॉ. अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय, खंड–5)

बाबा साहेब के जीवनी-लेखक स्वर्गीय श्री सी. बी. खैरमोड़े ने उनके शब्दों को उद्धृत किया है, जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण का परिचायक है– ''मुझमें और सावरकर में इस प्रश्न पर न केवल सहमति है, बल्कि सहयोग भी है कि हिंदू समाज को एकजुट और संगठित किया जाए, और हिंदुओं को अन्य मजहबों के आक्रमणों से आत्मरक्षा के लिए तैयार किया जाए।''

9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में बाबा साहेब ने कहा, ''इस देश का सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक उत्थान आज नहीं तो कल होगा ही, इस बारे में मुझे जरा भी संदेह नहीं है। आज सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से हम एक–दूसरे से अलग हो गए हैं, यह मैं जानता हूं, अभी हम एक–दूसरे से लड़ रहे हैं। लड़नेवाली एक छावनी का मैं भी एक नेता हूं। ऐसा हुआ तो भी उचित समय और उचित परिस्थिति आते ही यह विशाल देश एक हुए बिना कभी नहीं रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत उसकी एकता में आड़े नहीं आ सकती। इस देश में इतने पंथ और इतनी जातियां होने के बावजूद किसी न किसी तरह हम सारे लोग इकट्ठा होंगे ही, इस बारे में मेरे मन में जरा भी संशय नहीं है।"

बाबा साहेब ने 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में 'कास्ट इन इंडिया' प्रबंध प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने लिखा, ''भारत में सर्वव्यापी सांस्कृतिक एकता है। यद्यपि समाज अनगिनत जातियों में बंटा है फिर भी वह एक संस्कृति से बंधा हुआ है।''

संविधान सभी में 5 फरवरी 1950 को दिया गया उनका भाषण विचारशील है। उन्होंने कहा था, ''भारत शताब्दियों बाद स्वाधीन हुआ है। अब इस स्वराज्य की रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है। अपने समाज में किसी प्रकार की फूट पुनः हमसे स्वराज्य को छीन लेगी। शताब्दियों की गुलामी के परिणामस्वरूप हमसे कुछ विकृतियां,

ऊंच–नीच भेद, आर्थिक विषमता, पिछड़ापन, जातिवाद आदि उत्पन्न हुए हो सकते हैं, परंतु इसे अपना हथियार बनाकर कोई विदेशी हमारे स्वत्वों का अपहरण करना चाहेंगे तो हम उसे सहन नहीं करेंगे। हम उनकी यह आकांक्षा मिट्टी में मिला देंगे। यह हमारा घरेलू मामला है, इसलिए हम इससे आपस में निबटेंगे। अपने लाभ मात्र या सामाजिक दृष्टि से अवनत स्थिति से निकलने की इच्छा से हम किसी विदेशी के हस्तक नहीं बनेंगे। हमें अपने में उत्पन्न होने वाले जयचंदों से सावधान रहना होगा। अपने जिस राष्ट्र एवं समाज के हम अंग–उपांग है, उसके हित को ठीक प्रकार से पहचानें।''

अखंड भारत

डॉ. अंबेडकर अखंड भारत के समर्थक थे। उनका मानना था कि हममें इतने जाति–पंथ हैं, तो भी इसमें कोई संदेह नहीं कि हम एक

ही समुदाय हैं। भारत के विभाजन के लिए यद्यपि मुसलमानों ने लड़ाई की तो भी आगे कभी एक दिन उन्हें अपनी गलती महसूस होगी और उनको लगेगा एक 'अखंड भारत' ही हमारे लिए अच्छा है।

संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में 17 दिसंबर 1946 का वक्तव्य उनके प्रखर राष्ट्रीय व्यक्तित्व का दर्शन कराता है। उन्होंने कहा था, 'आज मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन करने के लिए आंदोलन छेड़ा है, दंगे-फसाद शुरू किए हैं, लेकिन भविष्य में एक दिन इसी लीग के कार्यकर्ता और नेता अखंड भारत के हिमायती बनेंगे, यह मेरी श्रद्धा हैं। भारत की अधिकांश सेना में जिन रियासतों ने भारत विरोधी षड्यंत्र करने की पहल की है, अतिरिक्त क्षेत्रीय निष्ठा दिखाई है, उनके दुष्ट प्रयासों का स्वतंत्र भारत के शासकों द्वारा पूरी तरह से कुचलना चाहिए।''

अनुच्छेद 370 का विरोध

डॉ. अंबेडकर अनुच्छेद 370 को राष्ट्रीय एकता में बाधक मानते थे। उन्होंने इस अनुच्छेद पर संविधान सभा की बहस में विरोध किया था। जब पं. जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर शेख अब्दुल्ला डॉ. अंबेडकर के पास गए तो उन्होंने यह कहकर शेख को उल्टे पांव लौटा दिया, ''आप चाहते हैं कि भारत कश्मीर में सीमाओं की रक्षा करे, सड़कें बनाए, खाद्यान्न की आपूर्ति करे और कश्मीर को भारत के साथ समान दर्जा मिले लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में भारत को न्यूनतम अधिकार हो। ऐसा स्वीकार करना देश के साथ धोखा होगा और एक कानून मंत्री के रूप में मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा।''

समान नागरिक संहिता का समर्थन

बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण देश के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना चाहते थे। 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में दिए गए भाषण में उन्होंने कहा, ''...मेरे मित्र श्री हुसैन इमाम ने पूछा है कि क्या भारत जैसे विशाल देश के लिए एक समान नागरिक संहिता का होना संभव और वांछनीय होगा? अब मुझे स्वीकार करना होगा कि इस सीधी–सी बात के कारण मुझे घोर आश्चर्य है कि इस देश में मानवीय संबंधों के लगभग हर पक्ष को अपनी सीमा में लिए हुए पहले ही एक समान विधि संहिता है। हमारे पास एक पूरी अपराध संहिता है जो पूरे देश में चलन में है और जो दंड संहिता और क्रीमिनल प्रोसीजर कोड में समाहित है। हमारे पास संपत्ति हस्तांतरण कानून है जो संपत्ति से जुड़े संबंधों का नियमन करता है और जो पूरे देश में चलन में है।... मैं ऐसे असंख्य कानूनों का हवाला दे सकता हूं जो यह साबित करेंगे कि इस देश में व्यावहारिक रूप में एक समान नागरिक संहिता है, जिसकी अंतर्वस्तु समान है और जो पूरे देश में लागू है। केवल एक क्षेत्र ऐसा है जिस पर दीवानी कानूनी अब तक अपनी पकड़ नहीं बना पाया है और वह है विवाह और उत्तराधिकार।''

इस मुद्दे पर बहस के दौरान कुछ मुस्लिम सदस्यों द्वारा यह आशंका प्रकट करने पर कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान मुसलमानों के विरुद्ध है, डॉ. अंबेडकर ने इस आशंका को निर्मूल करार देते हुए कहा था, ''मेरा दृढ़ विश्वास है कि किसी मुसलमान को कभी भी यह कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि समान नागरिक संहिता के निर्माताओं ने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को भारी आघात पहुंचाया है।''

भारत की राजभाषा संस्कृत हो

संस्कृत की वैज्ञानिकता को ध्यान में रखकर ही डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में संस्कृत का समर्थन किया। उन्होंने 10 सितंबर 1949 को डॉ. बी.वी. केसकर और नजीरूद्दीन अहमद के साथ मिलकर संस्कृत को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए संविधान सभा में एक संशोधन प्रस्तुत किया था,

आप चाहते हैं कि भारत कश्मीर में सीमाओं की रक्षा करे, सड़कें बनाए, खाद्यान्न की आपूर्ति करे और कश्मीर को भारत के साथ समान दर्जा मिले लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में भारत को न्यूनतम अधिकार हो। ऐसा स्वीकार करना देश के साथ धोखा होगा और एक कानून मंत्री के रूप में मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा।'

परंतु दुर्भाग्यवश वह संशोधन पारित नहीं हो सका। यह सर्वविदित है कि संविधान–सभा में जब राजभाषा को लेकर चर्चा हो रही थी तो डॉ. अंबेडकर व पंडित लक्ष्मीकांत मैत्र ने संस्कृत में धाराप्रवाह वार्तालाप किया।

आर्य बाहर से नहीं आए थे

डॉ. अंबेडकर आर्य आगमन को लेकर विदेशी आक्रमणकारी होने के सिद्धांत को नकारते हैं। उनके शब्दों में, ''आर्यों को विदेशी प्रजाति और भारत पर उनके आक्रमण का सिद्धांत मात्र एक मान्यता और धारणा है, इससे अधिक कुछ भी नहीं।'' वे अपने विश्लेषण के उपरांत यह लिखते हैं, ''कहना न होगा कि पाश्चात्य लेखकों ने आर्य प्रजाति का जो सिद्धांत दिया है वह हर तरह से धराशायी हो गया है। यह सिद्धांत वैज्ञानिक अनुसंधान का विकृत रूप है। इसे तथ्यों पर आधारित नहीं किया गया। इसके विपरीत यह सिद्धांत पूर्वकल्पित है और तथ्यों का चयन उसे प्रमाणित करने के लिए किया गया है।''

धार्मिक व्यक्तित्व

डॉ. अंबेडकर धर्म को आवश्यक मानते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि धर्म व अध्यात्म से ही शील पनपता है। मार्क्सवाद धर्महीनता के कारण उन्हें पसंद नहीं आता था। डॉ. अंबेडकर कहते थे, ''मैं धर्म पर विश्वास रखता हूं। धर्म के मूल्यों के बिना समाज का संघर्ष केवल ईर्ष्यालु व सत्तालिप्सु लोगों का एक क्षुद्र संघर्ष बन जाएगा। धर्म आशा देता है, विश्वास देता है, व्यवस्था देता है, अनुशासन देता है।'' भगवद्गीता के विषय में वे कहते हैं, ''गीता मेरे सत्याग्रह की प्रेरणा का स्रोत है।''

बौद्ध धर्म अंगीकार

बाबा साहब वंचितों की दयनीय दशा को बदलना चाहते थे। जब उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने का निश्चय किया तो क्रिश्चियन एवं इस्लामी जगत के नामचीन लोग उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए उनके पीछे पड़ गए। उन्हें ढेरों धन–दौलत का लालच भी दिया गया। तब उन्होंने कहा, ''मैं हिंदू धर्म छोड़ दूंगा, परंतु मैं ऐसे धर्म को अंगीकार करूंगा, जो हिंदुस्तान की धरती पर ही जनमा हो। मुझे ऐसा ही धर्म स्वीकार है, जो विदेशों से आयात किया हुआ नहीं हो। इसी कारण मैं बौद्ध धर्म अंगीकार करता हूं।''

13 अक्तूबर 1956 को नागपुर में बौद्धमत में दीक्षा लेने से एक दिन पूर्व डॉ. अंबेडकर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एक बार उन्होंने गांधीजी को कहा था कि यद्यपि वे उनसे छुआछूत मिटाने के प्रश्न पर मतभेद रखते हैं, पर समय आने पर ''मैं वही मार्ग चुनूंगा जो देश के लिए सबसे कम हानिकर हो। मैं बौद्धमत में दीक्षित होकर देश को सबसे बड़ा लाभ पहुंचा रहा हूं, क्योंकि बौद्धमत भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। मैंने सावधानी बरती है कि मेरे पंथ–परिवर्तन से इस देश की संस्कृति और इतिहास को कोई हानि न पहुंचे।'' (धनंजय कीर–कृत ''अंबेडकर : जीवन और लक्ष्य'', पृ. 498)

डॉ. अंबेडकर के कार्यों का संपूर्णता में आंकलन करे तो हम पाएंगे कि वे प्रखर राष्ट्रप्रेमी थे। उनके बारे में समग्रता से निरंतर अध्ययन करने और उनकी राष्ट्रीय दृष्टि को उभारने की आवश्यकता है। ■

मंत्रिमंडल ने यूरिया सब्सिडी को 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी जारी रखने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 14 मार्च को उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। दरअसल, यूरिया सब्सिडी योजना जारी रहने से ये सुनिश्चित हो सकेगा कि किसानों को वैधानिक नियंत्रित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध हो। उर्वरक क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन से हेराफेरी के मामले कम हो जाएंगे और उर्वरक की चोरी बंद हो जाएगी।

गौरतलब है कि उर्वरक विभाग देशभर में उर्वरक क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को लाने की प्रक्रिया में है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से किसानों को आर्थिक सहायता के साथ उर्वरक की बिक्री से उर्वरक कम्पनियों को शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। अतः यूरिया सब्सिडी योजना जारी रखने से उर्वरक क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का आसानी से कार्यान्वयन हो सकेगा।

उल्लेखनीय है कि यूरिया सब्सिडी 1 अप्रैल, 2017 से उर्वरक विभाग की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का हिस्सा है और बजटीय सहायता से सरकार पूरी तरह से इसका वित्तीय प्रबन्ध करती है। यूरिया सब्सिडी योजना जारी रहने से यूरिया निर्माताओं को समय पर सब्सिडी का भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। इसके परिणामस्वरूप किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध होगा। यूरिया सब्सिडी में आयातित यूरिया सब्सिडी शामिल है, जो देश में यूरिया की निर्धारित मांग और उत्पादन के बीच की खाई को पाटने के लिए आयात को सुधारने की तरफ संचालित है। इसमें देश में यूरिया को लाने-ले-जाने के लिए माल भाड़ा सब्सिडी भी शामिल है।

पृष्ठभूमि

रसायन उर्वरक ने खाद्यान्न उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह भारतीय कृषि के विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। निरन्तर कृषि विकास और संतुलित पोषक प्रयोग के लिए यूरिया वैधानिक नियंत्रित मूल्य पर किसानों को उपलब्ध कराया जाता है, जिसका मूल्य इस समय 5360/- रुपये प्रति मीट्रिक टन (नीम कोटिंग के लिए केन्द्रीय / राज्य कर और अन्य शुल्कों को हटाकर) है। खेत पर पहुंचाए गए उर्वरक के मूल्य और किसान द्वारा भुगतान किए गए अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच का अन्तर सरकार द्वारा उर्वरक निर्माता/आयातक को दी जाने वाली सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। इस समय 31 यूरिया निर्माण इकाईयां हैं, जिनमें से 28 यूरिया इकाईयां प्राकृतिक गैस (रसोई गैस/एलएनजी/सीबीएम का इस्तेमाल कर रही हैं) का इस्तेमाल फीडस्टॉक/ईंधन के रूप में और शेष तीन यूरिया इकाईयां नाप्था का इस्तेमाल फीडस्टॉक/ईंधन के रूप में कर रही हैं। ■

पीएमएवाई (शहरी) के तहत शहरी गरीबों के लिए 3,21,567 सस्ते घरों को स्वीकृति

4,753 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 18,203 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी गरीबों के लाभ के लिये 3,21,567 घरों के निर्माण के लिए 4,753 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 18,203 करोड़ रुपये निवेश को मंजूरी दी। यह स्वीकृति 26 मार्च को आयोजित केंद्रीय अनुमोदन और निगरानी समिति की 32 वीं बैठक में दी गई। हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार, केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और गोवा राज्यों के 523 शहरों में परियोजनाओं को स्वीकृति दी।

हरियाणा के 55 शहरों और कस्बों में 70,671 घरों के लिए 1,060 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 7,261 करोड़ रुपये के निवेश को स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल के 86 शहरों और कस्बों में 59,929 घरों के लिए 899 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता और 2,431 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। राजस्थान के 48 शहरों में 54,821 सस्ते घरों के लिए 822 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता और 2,519 करोड़ रुपये के निवेश को स्वीकृति दी गई। उत्तर प्रदेश के 121 शहरों और कस्बों में 39,683 घरों के लिए 595 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 1,059 करोड़ निवेश को स्वीकृति दी गई। गुजरात के 19 शहरों और कस्बों में 35,851 घरों के लिए 467 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 2,204 करोड़ रुपये निवेश को स्वीकृति दी गई। मिजोरम के 16 शहरों और कस्बों में 15,798 घरों के लिए 237 करोड़ की केन्द्रीय सहायता के साथ 316 करोड़ रुपये का निवेश किया गया।

राजस्थान के 48 शहरों में 54,821 सस्ते घरों के लिए 822 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता और 2,519 करोड़ रुपये के निवेश को स्वीकृति दी गई। उत्तर प्रदेश के 121 शहरों और कस्बों में 39,683 घरों के लिए 595 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 1,059 करोड़ निवेश को स्वीकृति दी गई।

कर्नाटक के 58 शहरों में 11, 941 सस्ते घरों के लिए 179 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता और 605 करोड़ रुपये के निवेश को स्वीकृति दी गई। महाराष्ट्र के 15 शहरों और कस्बों में 10,639 घरों के लिए 156 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 863 करोड़ रुपये के निवेश को स्वीकृति दी गई। मध्यप्रदेश के 11 शहरों और कस्बों में 5,426 घरों के लिए 81 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 289 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। बिहार के 10 शहरों में 8,154 सस्ते घरों के लिए 122 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 388 करोड़ के निवेश को स्वीकृति दी गई।

केरल के 32 शहरों और कस्बों में 5,073 घरों के लिए 76 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 203 करोड़ रुपये के निवेश को स्वीकृति दी गई। हिमाचल प्रदेश के 41 शहरों और कस्बों में 3,345 घरों के लिए 50 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 55 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। पंजाब के 1 शहर में 176 सस्ते घरों के लिए 2.7 करोड़ की केन्द्रीय सहायता के साथ 9 करोड़ रुपये के निवेश को स्वीकृति दी गई। गोवा के 10 शहरों में 60 घरों के लिए 2.43 करोड़ रुपये निवेश को स्वीकृति दी गई।

उपरोक्त प्रस्तावित घरों के साथ, सीएसएमसी के अंतिम अनुमोदन के बाद पीएमएवाई (शहरी) के तहत संचयी घर 42,45,792 हो जाएंगे। इसके अलावा आरएवाई योजना की परियोजनाओं को शामिल करने के बाद पीएमएवाई (शहरी) के तहत वित्त पोषित होने वाले घरों की कुल संख्या 43,87,640 हो जाएगी। 32 वें सीएसएमसी में गोवा की भागीदारी के साथ, सभी 35 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कस्बों और शहरों को पीएमएवाई (शहरी) मिशन के तहत शामिल किया गया है। ■

आमजन तक पहुंचाएं गुड गवर्नेंस का लाभः वसुंधरा राजे

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा कि राज्य सरकार का पूरा फोकस प्रदेश के समग्र विकास और जनता की तकलीफों को दूर करने पर है। इसके लिए चार साल में राज्य सरकार ने इतने काम किए हैं, जितने 50 साल में नहीं हुए। उन्होंने कहा कि युवा विकास प्रेरक सरकार की योजनाओं और गुड गवर्नेंस का लाभ आमजन तक पहुंचाने में प्रभावी भूमिका निभाएं।

श्रीमती राजे 23 मार्च को मुख्यमंत्री कार्यालय में ''युवा विकास प्रेरक समीक्षा एवं मार्गदर्शन'' कार्यक्रम में आये युवा विकास प्रेरकों को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने युवा विकास प्रेरकों से कहा कि जानकारी के अभाव में लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता। इसलिए इस विकास यात्रा में आप जैसे युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। श्रीमती राजे ने युवा विकास प्रेरकों की अब तक की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि आगे भी इसी तरह पूरे उत्साह के साथ जुटे रहें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार विकास विरोधी तत्व अफवाहें फैलाकर या मीडिया के विभिन्न माध्यमों के जरिए लोगों को उकसाने या भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, इससे विकास में बाधा पैदा होती है। युवा विकास प्रेरक लोगों से सतत संवाद कर इस दुष्प्रचार के प्रति उन्हें जागरूक करें। उन्होंने कहा कि युवा विकास प्रेरक राज्य सरकार को जनता के फीडबैक से भी अवगत कराएं, ताकि लोगों की परेशानियों को दूर करने में आसानी हो।

श्रीमती राजे ने युवा प्रेरकों से सीधा संवाद करते हुए पिछले 17 माह में जनता के बीच जाकर उनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी ली। युवा विकास प्रेरकों ने फील्ड में किए गए विभिन्न नवाचारों एवं उनके अनुभवों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने युवा विकास प्रेरकों के सकारात्मक प्रयासों को सराहा। उन्होंने कहा कि आपके सामने कई तरह की चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप एक मिशन के रूप में आगे बढ़ेंगे, तो प्रदेश को विकास का शिखर छूने से कोई नहीं रोक सकता।

युवा नेट लॉन्च किया

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 'युवा नेट' लॉन्च किया। इस 'एनी टाइम प्लेटफॉर्म' के माध्यम से लाखों युवा सीधे मुख्यमंत्री से संवाद कर सकेंगे।

इससे पहले युवा विकास कार्यक्रम की सलाहकार समिति की अध्यक्ष तथा राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष डॉ. ज्योति किरण ने पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से युवा विकास प्रेरकों की गतिविधियों, उपलब्धियों एवं आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। आयोजना विभाग के निदेशक श्री ओपी बैरवा ने सभी का आभार व्यक्त किया। ■

सिंचाई क्षमता बढ़ाने हेतु खर्च होंगे एक लाख दस हजार करोड़: शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोक सभा और विधान सभा के चुनाव एक साथ होना चाहिये। इसके लिये संविधान में संशोधन होना चाहिये। इससे सत्ताधारी राजनैतिक दलों को विकास योजनाएं बनाने और उन्हें अच्छी तरह लागू करने का समय मिलेगा। उन्होंने कहा कि बार-बार चुनावों से धन और ऊर्जा दोनों का क्षय होता है। प्रयोग के तौर पर प्रदेश में पंचायतों, नगरीय निकायों, सहकारिता संस्थाओं, जल उपभोक्ता संस्थाओं और अन्य संस्थाओं के चुनाव एक साथ कराने पर विचार किया जायेगा। श्री चौहान 25 मार्च को भोपाल में एक न्यूज चैनल द्वारा आयोजित बिजनेस लीडर्स समिट को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई क्षमता बढ़ाने पर एक लाख दस हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। अगले पांच सालों में सिंचाई क्षमता बढ़ाकर 80 लाख हेक्टेयर की जायेगी। उन्होने कहा कि मध्यप्रदेश का अभूतपूर्व विकास हुआ है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। विकास दर पिछले तेरह सालों में दो अंकों में रही है।

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की 65 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। किसानों ने अभूतपूर्व कृषि उत्पादन दिया है। कृषि उत्पादन अब समस्या नहीं रही। अब किसानों को सही मूल्य दिलाने की चुनौती है। इसके लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य, भावांतर भुगतान योजना और मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना जैसे बेहतर विकल्प उपलब्ध कराये गये है। उन्होंने कहा कि भावांतर भुगतान योजना को पूरे देश में लागू करने पर केन्द्र विचार कर रहा है।

बासमती चावल के मुददे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसान 1908 से बासमती चावल का उत्पादन कर रहे हैं। कनाडा और अमेरिका में जितना बासमती चावल का निर्यात होता है, उसमें 50 प्रतिशत सिर्फ मध्यप्रदेश से हो रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ निर्यातकों और विशेष रूप से पाकिस्तान को यह पसंद नहीं कि मध्यप्रदेश के बासमती चावल को भौगोलिक पहचान का प्रमाणपत्र मिले। बासमती उत्पादक किसानों के लिये पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे।

श्री चौहान ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने से राज्यों का राजस्व आधार मजबूत हुआ है। राज्य को केन्द्रीय करों और अन्य योजनाओं में एक लाख करोड़ रुपये मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री असंगठित क्षेत्र श्रमिक कल्याण योजना देश की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना है। श्रमिकों के बच्चों की पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई-लिखाई, श्रमिकों का मुफ्त इलाज जैसी सुविधाएं मिलेंगी। उन्हें 2022 तक पक्का मकान मिलेगा। वे आवासीय जमीन के मालिक होंगे।

पूर्ण शराबबंदी के बारे में अपने विचार रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सामाजिक जन-जागरण से जुड़ा विषय है। इसकी हानि के प्रति जागरूकता बढ़ाकर इसे पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। कानून व्यवस्था के संबंध में उन्होंने कहा कि सरकार गुंडों के लिये कठोर है। गुंडों को सबक सिखाने में नागरिकों का सहयोग चाहिये। श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं के स्व-सहायता समूहों के परिसंघों को पोषण आहार तैयार करने की निर्माण इकाईयों का संचालन सौंपने का फैसला लिया गया है। अगले छह महीनों में महिला स्व-सहायता समूहों के परिसंघ पोषण आहार कारखानों का संचालन करने की स्थिति में होंगे। ■

चौपालों और समाधान शिविरों के जरिये जनता से सीधा संवाद

आम जनता के साथ सीधे संवाद और योजनाओं के सोशल आडिट के लिए अनोखा 'लोक सुराज अभियान' छत्तीसगढ़ में प्रदेशवासियों की सक्रिय भागीदारी से उत्साह के साथ चल रहा है। इस वर्ष लगभग ढाई महीने पहले शुरू हुए राज्य सरकार के इस वार्षिक अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का प्रदेशव्यापी तूफानी दौरा अब भी जारी है। यह अभियान राज्य सरकार और जनता के बीच अपनेपन से परिपूर्ण भावनात्मक रिश्तों का पर्याय बन गया है, जहां चौपालों और समाधान शिविरों में लोग सरकार के नुमाइंदों से खुलकर बातचीत करते हुए अपना दुःख दर्द बता रहे हैं और उन्हें राहत भी मिल रही है। रमन सरकार इस अभियान के जरिये प्रदेश की 10 हजार 971 ग्राम पंचायतों के लगभग 20 हजार गांवों और सभी 168 शहरों में जनता से संवाद कायम कर रही है। चौपाल और समाधान शिविर सरकार और जनता के बीच संवाद सेतु की भूमिका निभा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि अभियान का यह तीसरा चरण है। इसमें मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री और मुख्य सचिव से लेकर सभी संभागीय कमिश्नर, जिला कलेक्टर और शासन के सभी विभागों के मैदानी अधिकारी और कर्मचारी गांवों का दौरा कर रहे हैं। समाधान शिविरों में लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में लोक सुराज अभियान का पहला अध्याय ग्राम सुराज अभियान के रूप में वर्ष 2005 में शुरू हुआ। लगभग सात वर्ष बाद उन्होंने इसमें नगर सुराज अभियान को भी जोड़ा। इसके बाद वर्ष 2015 से ग्राम और नगर दोनों को मिलाकर उनके नेतृत्व में लोक सुराज अभियान की शुरुआत हुई। डॉ. सिंह ने इस बार भी लोक सुराज अभियान में हेलीकॉप्टर से जिलों के आकस्मिक दौरे की शुरुआत राज्य के नक्सल हिंसा पीड़ित बस्तर संभाग के जिलों से की। उन्होंने पहले दिन 11 मार्च को कांकेर जिले के ग्राम बण्डाटोला में आकस्मिक रूप से पहुंचकर चौपाल लगाई और उसी दिन मद्देड़ (जिला बीजापुर) और इंजरम (जिला सुकमा) के समाधान शिविरों में भी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने लोक सुराज के सोलहवें दिन बेमेतरा, बालोद, धमतरी और कांकेर जिलों का सघन दौरा किया। इसे मिलाकर डॉ. सिंह ने विगत लगभग एक पखवाड़े से चल रहे तीसरे चरण के अभियान में बस्तर से लेकर सरगुजा तक राज्य के 27 में से 25 जिलों का दौरा कर लिया है।

उल्लेखनीय है कि डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में इस वर्ष का लोक सुराज अभियान 12 जनवरी से शुरू हुआ है, जो तीन चरणों में 31 मार्च तक चल रहा है। पहले चरण में 12 जनवरी से 14 जनवरी तक ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में शिविर लगाकर लोगों से आवेदन संकलित किए गए। दूसरे चरण में 15 जनवरी से 11 मार्च तक उनका निराकरण किया गया और तीसरे चरण में 11 मार्च से 31 मार्च के बीच ग्राम समूहों और शहरी क्षेत्रों में वार्ड समूहों के बीच समाधान शिविर लगाकर लोगों को उनके आवेदनों के निराकरण की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है।

हितग्राही मूलक योजनाओं में चेक और अनुदान सामग्री का भी वितरण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ देश का पहला और इकलौता राज्य है, जहां मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शासन और प्रशासन के पदाधिकारी और प्रतिनिधि हर साल लगभग ढाई महीने से तीन माह का समयबद्ध अभियान चलाकर जनता के बीच पहुंचते हैं और लोगों का दुःख दर्द सुनकर उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं के जरिए राहत दिलाने का भी प्रयास करते हैं। इसके साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति का भी आंकलन आम जनता के बीच बैठकर कर लिया जाता है। ■

प्रदेश सरकार ने एक वर्ष में किए महत्वपूर्ण कार्य : दिनेश शर्मा

प्रदेश सरकार द्वारा निरन्तर किये जा रहे विकास कार्यों से एक–दो वर्ष में आगरा की दिशा और दशा दोनों बदल जायेगी। जब वर्तमान सरकार सत्ता में आयी थी तब प्रदेश सरकार की स्थिति अच्छी नहीं थी, वर्तमान सरकार ने कानून का राज्य स्थापित किया, जो माफिया गुण्डे थाने में जाकर धमकी देते थे, वे आज जेल से अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं तथा भविष्य में गुनाह न करने की बात कहते है। आज उ.प्र. में कई उद्योगपति फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार हो गये हैं।

यह विचार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने आगरा कालेज के गंगाधर शास्त्री हाल में आयोजित उ.प्र. सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सम्पूर्ण विकास हेतु प्रदेश सरकार ने एक वर्ष में अनेक महत्वपूर्ण व जनकल्याणकारी कार्य किये हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बिना पुलिस के हस्तक्षेप के नकल विहीन परीक्षा कराई गई है। परीक्षा में 11 लाख परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा को छोड़ दिया, इन छात्रों में अधिकांश ऐसे थे जो बाहर के प्रदेशों के थे, जो यहां केवल परीक्षा देने आते थे। उन्होंने कहा कि नकल विहीन परीक्षा के पश्चात् अब माध्यमिक शिक्षा परिषद में व्यापक परिवर्तन किया जा रहा है। नया सत्र एक अप्रैल से प्रारम्भ किया जायेगा तथा एन.सी.आर.टी. के तर्ज पर कोर्स में भी परिवर्तन किया जा रहा है तथा प्रदेश में 166 नये दीन दयाल उपाध्याय मॉडल स्कूल व अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में 42 मॉडल स्कूल अलग से खोला जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को भी उच्चस्तरीय एवं गुणवत्ता युक्त बनाने की है। उन्होंने कहा कि जनपद आगरा का प्रभारी मंत्री होने के कारण मुझे आगरा से लगाव भी अधिक है। आगरा को स्मार्ट सिटी के रुप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही अमृत योजना के अन्तर्गत शीघ्र ही गंगा जल भी मिलने लगेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के हित में कार्य करते हुए ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत उनके एक लाख रुपये तक के ऋण को माफ किया है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष को सरकार ने इस व्यवस्था को ठीक करने में लगाया है। अगला वर्ष व्यापारियों व विद्यार्थियों के लिए रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योग–धन्धें लगेंगे और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सरकार ने सरकारी विभागों में भर्तियों के लिए विज्ञापन निकाले हैं और विज्ञापन शीघ्र निकाले जाएगें, जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। सरकार ने गेंहूं का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए कार्य कर रही है।

जनपद आगरा के लिए प्रदेश सरकार के साथ–साथ केन्द्र सरकार ने भी अनके कार्य किये है जहां एक ओर आगरा से इटावा बटेश्वर तक रेल सेवा प्रारम्भ की गई है, वहीं दूसरी ओर आगरा से जयपुर शताब्दी एक्सप्रेस, आगरा से दिल्ली तक गतिमान एक्सप्रेस तथा आगरा से एटा के लिए पैसेन्जर चालू की गई है। आगरा–बरेली हाइवे के लिए 1000 करोड़ रुपये दिये जाने के साथ ही आगरा एयरपोर्ट के लिए भी धनराशि दी गई है।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष प्रो. रामशंकर कठेरिया ने कहा कि जनपद आगरा के लिए प्रदेश सरकार के साथ–साथ केन्द्र सरकार ने भी अनके कार्य किये है जहां एक ओर आगरा से इटावा बटेश्वर तक रेल सेवा प्रारम्भ की गई है, वहीं दूसरी ओर आगरा से जयपुर शताब्दी एक्सप्रेस, आगरा से दिल्ली तक गतिमान एक्सप्रेस तथा आगरा से एटा के लिए पैसेन्जर चालू की गई है। आगरा–बरेली हाइवे के लिए 1000 करोड़ रुपये दिये जाने के साथ ही आगरा एयरपोर्ट के लिए भी धनराशि दी गई है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही आगरा में पं. दीन दयाल उपाध्याय जी के नाम पर एयरपोर्ट की स्थापना होगी। उन्होंने बताया कि आगरा के लिए रबर डैम के स्थान पर बैराज स्वीकृत किया गया है। आगरा में पासपोर्ट कार्यालय प्रारम्भ हो चुका है और शीघ्र मैट्रो का कार्य भी प्रारम्भ हो जायेगा। आगरा में हाईकोर्ट ब्रेंच लाने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। ■

भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर

भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) ने 12 मार्च को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। दरअसल, दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 में समयबद्ध ढंग से कॉरपोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और विभिन्न लोगों के दिवाला संबंधी समाधान का उल्लेख किया गया है, ताकि इस तरह के व्यक्तियों की परिसम्पत्तियों के मूल्य को अधिकतम किया जा सके। इस संहिता में उद्यमिता को बढ़ावा देने, ऋण उपलब्ध कराने एवं समस्त हितधारकों के हितों में संतुलन बैठाने का भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए एक संस्थागत बुनियादी ढांचा स्थापित किया गया है जिसमें निर्णयन प्राधिकरण, आईबीबीआई, दिवाला प्रोफेशनल, दिवाला प्रोफेशनल एजेंसियां और सूचना उपक्रम शामिल हैं। इस संहिता में विभिन्न प्रक्रियाओं यथा दिवाला समाधान, कंपनी के परिसमापन, व्यक्तिगत दिवाला समाधान और व्यक्तिगत दिवालियेपन से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है।

आरबीआई और आईबीबीआई दोनों ही एक त्वरित एवं दक्ष समाधान प्रक्रिया के जरिए इस संहिता और इससे संबद्ध नियमों एवं विनियमनों के प्रभावकारी क्रियान्वयन में काफी दिलचस्पी रखते हैं। यही कारण है कि इन दोनों ने एमओयू के तहत एक-दूसरे की सहायता करने और आपस में सहयोग करने पर सहमति जताई है, ताकि इस संहिता का प्रभावकारी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि, इस संदर्भ में लागू किए जा चुके कानूनों द्वारा तय की गई सीमाओं को भी ध्यान में रखना होगा।

उपर्युक्त एमओयू में इन बातों का उल्लेख किया गया है: (ए) दोनों पक्षों के बीच सूचनाओं को साझा करना, जिसके लिए पहले से ही लागू कानूनों द्वारा तय की गई सीमाओं को भी ध्यान में रखना होगा, (बी) उपलब्ध संसाधनों को एक-दूसरे के साथ उस हद तक साझा करना जिसकी कानूनन अनुमति दी गई है, (सी) आपसी हितों के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए समय-समय पर बैठकें आयोजित करना (डी) एक-दूसरे के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, ताकि सामूहिक संसाधनों के कारगर उपयोग के लिए हर पक्ष को दूसरे पक्ष के मिशन से भली-भांति अवगत कराया जा सके, (ई) दिवाला प्रोफेशनलों और वित्तीय ऋणदाताओं का क्षमता निर्माण करना और (एफ) संहिता के प्रावधानों, इत्यादि के तहत विभिन्न प्रकार के संकटग्रस्त कर्जदारों की त्वरित दिवालिया समाधान प्रक्रिया की अहमियत और आवश्यकता के बारे में वित्तीय ऋणदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करना। ■

अगले चार वर्षों में आईआईटी, एनआईटी को 1 लाख करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता: डॉ. सत्यपाल सिंह

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) राज्य मंत्री श्री सत्यपाल सिंह ने 19 मार्च, 2018 को आईआईटी भुवनेश्वर के छठे दीक्षांत समारोह में कहा कि आईआईटी जैसे संस्थानों को भी उच्च शिक्षा के 100 शीर्ष वैश्विक संस्थानों में अपना स्थान बनाना चाहिए। मंत्री महोदय ने कहा कि इस दिशा में कई तरह के प्रयास किये जाने चाहिए जैसेकि भारतीय संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों एवं संकाय (फैकल्टी) की मौजूदगी होनी चाहिए, इनमें अनुसंधान एवं नवाचार विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के अनुरूप होने चाहिए, इनमें भौतिक सुविधाएं किसी से भी कमतर नहीं होनी चाहिए।

श्री सिंह ने बताया कि उनका मंत्रालय तकनीकी शिक्षा में और अधिक गुणवत्ता और उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी प्रणालियों के पुनरुत्थान (राइज) का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य अगले चार वर्षों के दौरान आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसईआर को एक लाख करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता मुहैया कराना है।

मंत्री महोदय ने कहा कि हमारा देश प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार 'नए भारत' के लिए राष्ट्र निर्माण में मदद हेतु इन प्रतिभाशाली युवाओं पर भरोसा कर रहा है। उन्होंने कहा कि रोबोटिक्स, वर्चुअल रियल्टी, क्लाउड टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) और अन्य प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के जरिए भारत में निकट भविष्य में चौथी औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात होने के आसार नजर आ रहे हैं।

मंत्री महोदय ने अत्यधिक महत्व की बुनियादी बातों से लेकर अप्लायड क्षेत्रों तक के विस्तृत विषयों, विशेषकर लाल मिट्टी और फ्लाई ऐश का इस्तेमाल कर पर्यावरण अनुकूल भू-बहुलक (जियो-पॉलीमर) कंक्रीट के विकास के लिए औद्योगिक कचरे के उपयोग पर आईआईटी भुवनेश्वर में किए गए अनुसंधान कार्यों की सराहना की। भू-बहुलक कंक्रीट का उपयोग पर्यावरण अनुकूल इमारतों, पुलों, सड़कों और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसंपत्तियों के निर्माण में किया जा सकता है। ■

ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय का उपयोग 93 % से ज़्यादा

विश्व बैंक समर्थित स्वच्छ भारत मिशन परियोजना के अंतर्गत एक स्वंतत्र सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किये गए राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 -18 में ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय का उपयोग 93.4% होने की पुष्टि हुई है। अर्थात्, जिन घरों में शौचालय उपलब्ध है, उनमें से 93.4% उसका उपयोग भी करते हैं।

जिन गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित और सत्यापित किया गया है, स्वंतत्र सर्वेक्षण एजेंसी ने उनमें से 95.6 % गांवों के खुले में शौच मुक्त होने की भी पुष्टि की है। यह सर्वेक्षण मध्य-नवम्बर 2017 और मध्य-मार्च 2018 के बीच किया गया और इसके अंतर्गत 6136 गावों के 92040 घरों का स्वच्छता सम्बन्धी विषयों पर सर्वेक्षण किया गया।

सर्वेक्षण के अंतर्गत गांवों के स्कूल, आंगनवाड़ी एवं सामुदायिक शौचालयों का भी सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण का संपूर्ण कार्य कंप्यूटर सहायतित व्यक्तिगत साक्षात्कार (कैपी) नामक प्लेटफार्म के माध्यम से सम्पादित किया गया।

राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के मुख्य परिणाम निम्नवत हैं :

1. सर्वेक्षण किये गए 77 % घरों में शौचालय की सुविधा पायी गयी
2. शौचालय की सुविधा वाले घरों में से 93.4 % में शौचालय का उपयोग
3. सर्वेक्षण किये गए खुले में शौच से मुक्त घोषित एवं सत्यापित गांवों में से 95.6 % के खुले में शौच से मुक्त होने की पुष्टि
4. सर्वेक्षण किये गए गांवों में से 70 % में ठोस तथा तरल अपशिष्ट की न्यूनतम मात्रा पायी गयी

उक्त परिणाम स्वंतत्र सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के प्रबंधन हेतु गठित एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप (EWG) के समक्ष प्रस्तुत किये गए। EWG में विश्व बैंक, यूनिसेफ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इंडिया सैनिटेशन कोएलिशन, सुलभ इंटरनेशनल, नॉलेज लिंक्स समेत नीति आयोग एवं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सदस्य हैं। EWG ने सर्वेक्षण के सफल क्रियान्वयन पर अपनी संतुष्टि ज़ाहिर की है। स्वच्छता सर्वेक्षण एजेंसी ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को अपनी अंतरिम रिपोर्ट और सर्वेक्षण से सम्बन्धी आंकड़े दिए हैं, जिसे मंत्रालय के वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन ने अब तक करोड़ों लोगों के व्यवहार परिवर्तन करने में सफलता हासिल की है। स्वच्छ भारत मिशन के प्रारम्भ से अब तक करोड़ों लोगों ने अपने शौचालय का निर्माण किया है और उसका नियमित इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तक 6.5 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है और 3.38 लाख गांव और 338 ज़िले अब तक खुले में शौच से मुक्त घोषित हुए हैं। 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, नामतः सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, चंडीगढ़, दमन और दीउ एवं दादरा और नगर हवेली, खुले में शौच मुक्त घोषित किये जा चुके हैं। ■

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक औषधि प्रणालियों के क्षेत्र में भारत और ईरान के बीच सहयोग के लिए समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 14 मार्च को पारंपरिक औषधि प्रणालियों के क्षेत्र में भारत और ईरान के बीच सहयोग के लिए समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी। इससे समझौता ज्ञापन से पारंपरिक औषधि क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक धरोहर के मद्देनजर यह समझौता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

गौरतलब है कि भारत को सुविकसित पारंपरिक औषधि प्रणालियों का वरदान प्राप्त है, जिसमें जड़ी-बूटियां शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य परिदृश्य में इसकी अपार क्षमता मौजूद है। भारत और ईरान के बीच कई विशेषताएं समान हैं उनकी भाषा, संस्कृति और परंपराओं में समानता है तथा दोनों ही देश जड़ी-बूटियों का समान रूप से प्रयोग करते हैं। दोनों देशों में वृहद जैव-विविधता मौजूद है और पारंपरिक औषधि प्रणालियों का प्रायः इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ही देशों में दुर्लभ औषधीय पौधे पाए जाते हैं। इसके अलावा ईरान, पारंपरिक औषधि प्रणाली के क्षेत्र में भारत की अग्रणी देश की स्थिति को मान्यता देता है। भारत में इस क्षेत्र में मजबूत संरचना मौजूद है और यहां उत्कृष्ट उत्पादन ईकाईयां काम करती हैं।

यूजीसी ने एक ऐतिहासिक निर्णय में 60 उच्च शिक्षा संस्थान को स्वायत्तता दी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एक ऐतिहासिक निर्णय में ऐसे 60 उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान की, जिन्होंने उच्च शैक्षणिक मानदंडों को बरकरार रखा है। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 20 मार्च को नई दिल्ली में इसकी घोषणा की। श्री जावडेकर ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में उदार व्यवस्था लागू करने का प्रयास कर रही है और गुणवत्ता के साथ स्वायत्तता पर जोर दे रही है।

इसका और विवरण देते हुए श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जिन 60 उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता दी गई है, उनमें 52 विश्वविद्यालय शामिल हैं। इन 52 विश्वविद्यालयों में 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 21 राज्य विश्वविद्यालय, 24 डीम्ड विश्वविद्यालय और 2 निजी विश्वविद्यालय हैं। श्री जावडेकर ने कहा कि ये विश्वविद्यालय यूजीसी के अधीन बने रहेंगे, लेकिन उन्हें नए पाठ्यक्रम, ऑफ कैम्पस केंद्र, कौशल विकास कोर्स, शोध पार्क और अन्य शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने की स्वतंत्रता रहेगी। उन्हें विदेशी संकाय रखने, विदेशी विद्यार्थियों के पंजीकरण, संकाय को प्रोत्साहन आधारित परिलब्धियां देने, शैक्षणिक भागीदारियां करने और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने की आजादी होगी।

श्री जावडेकर ने कहा कि 8 महाविद्यालयों को भी स्वायत्तता दी गई है। 8 स्वायत्त महाविद्यालय अपना पाठ्यक्रम शुरू, परीक्षाएं कराने, मूल्यांकन करने के साथ ही परिणाम घोषित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इस मामले में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा सिर्फ डिग्री ही दी जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि उन तीन डीम्ड विश्वविद्यालयों को कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा, जिनकी गुणवत्ता में कमी बनी हुई है। उच्च शिक्षण संस्थानों की सूची निम्नलिखित है, जिन्हें यूजीसी ने स्वायत्तता प्रदान की है।

ग्रेडेड स्वायत्तता पर यूजीसी के नियमों के तहत विश्वविद्यालयों का वर्गीकरण

विश्वविद्यालय का प्रकार	श्रेणी I	श्रेणी II	कुल
केंद्रीय विश्वविद्यालय	2	3	5
राज्य विश्वविद्यालय	12	9	21
डीम्ड विश्वविद्यालय	11	13	24
निजी विश्वविद्यालय	0	2	2
स्वायत्त महाविद्यालय			8
कुल	25	27	60

ग्रेडेड स्वायत्तता के अनुदान के लिए विश्वविद्यालय

केंद्रीय विश्वविद्यालय

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	एनएएसी अंक	नियमों के अंतर्गत श्रेणी
1.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली	3.77	I
2.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	3.72	I
3.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी	3.41	II
4.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	3.35	II
5	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, तेलंगाना	3.26	II

पत्र-पत्रिकाओं से...

उच्च शिक्षा की नई उड़ान

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के साथ संस्थानों की आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में सरकार का यह बड़ा फैसला है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने जेएनयू, बीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद समेत देश के 62 उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्त घोषित कर दिया है। इन संस्थानों को अपने फैसले लेने के लिए अब यूजीसी पर निर्भर नहीं रहना होगा। ये अब खुदमुख्तार होंगे। सरकार का दावा तो यही है कि इन संस्थानों की शैक्षिक गुणवत्ता और इसे बनाए रखने में इनकी निरंतरता को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। माना गया है कि ये संस्थान अपने बूते अपनी दिशा खुद तय कर सकते हैं और स्वाभाविक रूप से ऐसे में उन्हें अपना खर्च भी खुद उठाने में सक्षम बना दिया जाना चाहिए। यानी नए फैसले के बाद ये अपनी दाखिला प्रक्रिया, फीस संरचना और पाठ्यक्रम भी खुद ही तय कर सकेंगे। एक झटके में मान भी लिया जाए कि शैक्षिक उदारवाद का यह प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने वाला होगा, लेकिन यह सब करते वक्त यह भी तो सुनिश्चित करना ही होगा कि वाकई यह कदम रचनात्मक बदलाव लाने वाला ही साबित हो।

– (हिन्दुस्तान, १३ मार्च, २०१८)

मोदी सरकार ने पुराने और अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को खत्म करके दी आमजन को राहत

यह अच्छी बात है कि पुराने और अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को खत्म करने की पहल के तहत केंद्र सरकार कुछ और ऐसे ही कानूनों को समाप्त करने की तैयारी में है। मोदी सरकार ने कुल 1824 ऐसे कानून चिन्हित किए थे जो पुराने और अप्रासंगिक हो चुके थे। इनमें से अब तक 1657 को खत्म किया जा चुका है। चूंकि अब अनुपयोगी कानूनों की संख्या 167 ही रह गई है इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि अगले एक वर्ष में उनसे भी मुक्ति मिल जाएगी और इस तरह सरकार अपने एक अन्य एजेंडे को पूरा कर लेगी। निःसंदेह इसके बाद सरकार इसे अपनी एक उपलब्धि बता सकती है, लेकिन बेहतर होगा कि वह आम जनता को इससे भी परिचित कराए कि अभी तक पुराने कानूनों को खत्म करने से शासन-प्रशासन को गति देने अथवा लोगों की समस्याओं का समाधान करने में कितनी मदद मिली है? जिन कानूनों की प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है उन्हें तो खत्म होना ही चाहिए, लेकिन इसी के साथ उन कानूनों को दुरुस्त करने का भी काम किया जाना चाहिए जो समस्याओं का समाधान करने में सहायक बनने के बजाय उन्हें उलझाने का काम करते हैं।

– (दैनिक जागरण, १६ मार्च,२०१८)

ईवीएम विरोध का राग

इससे निराशाजनक और कुछ नहीं हो सकता कि जब देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी कांग्रेस से यह उम्मीद की जा रही थी कि वह अपने अधिवेशन के जरिए पार्टी और साथ ही देश को कोई राह दिखाने या फिर उत्साहित करने का काम करेगी, तब उसके नेताओं की ओर से घिसी-पिटी बातों पर ही ज्यादा जोर दिया गया। इस क्रम में सबसे हैरानी इस पर रही कि राजनीतिक प्रस्ताव के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम पर हमला बोला गया। कांग्रेस ने ईवीएम पर निशाना साधते हुए जिस तरह मत पत्र के जरिए मतदान कराने की मांग की, उससे उसने अपनी संकुचित सोच का ही परिचय दिया।

ईवीएम पर सवाल उठाना एक गैरजरूरी मसले को तूल देने के अलावा और कुछ नहीं। यह केवल जनता को गुमराह करने के मकसद से किया जा रहा है, क्योंकि बहुत दिन नहीं हुए जब गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेसी नेताओं ने ही ईवीएम पर भरोसा जताया था। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या ईवीएम इसलिए अविश्वसनीय हो गई कि गोरखपुर और फूलपुर में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई? क्या कांग्रेस ने यह मान लिया है कि उसका चुनावी भविष्य उज्ज्वल नहीं और इसीलिए वह उस ईवीएम को खलनायक बनाने पर आमादा है जिसका चलन खुद उसके समय में शुरू हुआ था? अगर ईवीएम भरोसेमंद नहीं थी तो वह 2004 में सत्ता में कैसे आई? सवाल यह भी है कि अगर उसे ईवीएम में खोट दिख रही थी तो उसने दस साल के अपने शासन के दौरान मत पत्र से चुनाव क्यों नहीं कराए?

– (नई दुनिया, 19 मार्च, २०१८)

स्फुट विचार...

भारत की जनसंख्या को स्थिर करने की आवश्यकता है। निरन्तर बढ़ती जा रही जनसंख्या की आवश्यकताओं को निश्चल राष्ट्रीय संसाधनों से पूरा नहीं किया जा सकता है। भारत को अविलम्ब ही राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की आवश्यकता है।

— कुशाभाऊ ठाकरे

इतिहास में हुई भूल के लिए आज किसी से बदला लेने का समय नहीं है, लेकिन उस भूल को ठीक करने का सवाल है।

— अटल बिहारी वाजपेयी

प्रस्तुति: पंकज आनंद

आज ही लीजिए

कमल संदेश

की सदस्यता

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

और

दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

भाजपा के नवनिर्मित मुख्यालय 6ए, पं. दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली में भाजपा सांसदों को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

नई दिल्ली में भाजपा सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेतागण

मिजोरम में चकमा स्वायत्त जिला परिषद् परिवर्तन रैली में असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल व अन्य नेताओं के साथ भाजपा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री रामलाल

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20